नई समाजवादी क्रान्ति का उद्घोषक

बिगुल

मासिक समाचार पत्र • वर्ष 3 अंक 5
जून 2001 • तीन रुपये • बारह पृष्ठ

इंडियन लेबर कांफ्रेंस का संदेश क्या है?

सम्पादक

दिल्ली। विगत मई माह में आयोजित इंडियन लेबर कांफ्रेंस ने एक बार फिर मजदूर हितों की बात करने वाले ट्रेड यूनियनों की क़लई खोलकर रख दी और राजग सरकार के मजदूर विरोधी चरित्र को उजागर कर दिया। पिछली 18-19 मई को राजधानी दिल्ली में मज़दूरों, मालिकों और सरकार के प्रतिनिधियों का दो दिवसीय 37वीं त्रिपक्षीय बैठक (इसे ही इंडियन लेबर कांफ्रेंस कहा जाता है) हुई। इसमें पांच प्रमुख केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों – इंटक, एटक, सीटू, बी.एम.एस. तथा हिन्द मज़दूर सभा के प्रतिनिधि और भारतीय नियोक्ता परिषद (कारखाना मालिकों की संस्था) के प्रतिनिधियों के साथ-सरकार की ओर से खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी और श्रममंत्री सत्यनारायण जटिया अन्य नौकरशाहों के साथ शामिल हुए। सम्मेलन में इसके अतिरिक्त दूसरे श्रम आयोग के अध्यक्ष रवीन्द्र वर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी शामिल थे। इस सम्मेलन ने देश के मजदूर वर्ग को क्या सन्देश दिया, यह जानना मजदूर आन्दोलन के लिए महत्वपूर्ण है।

सम्मेलन का पहला दिन खत्म होने पर भारतीय मजदूर संघ के महासचिव हंसमुख भाई दवे ने अखबार वालों को यह जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि

श्रम सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये भाषण का सबसे अहम संदेश यह है कि सरकार हर हालत में, हर कीमत पर निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों पर बेरोकटोक आगे बढ़ती रहेगी। हर क़ीमत पर श्रम कानूनों में बदलाव कर मजदूरों को पूंजीपतियों का गुलाम बना दिया जाएगा, जिससे वे खून का आखिरी बूंद तक निचोड़ कर अपना मुनाफा पीटते रहें।

जब तक दूसरे श्रम आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक औद्योगिक विवाद अधिनियम और ठेका मजदूर कानून में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रधानमंत्री का यह आश्वासन श्रम मंत्री सत्यनारायण जटिया के उस बयान के ठीक उलट था जिसमें उन्होंने कहा था कि इन दोनों कानूनों में संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसद के मानसून सत्र (जुलाई में शुरू होने वाले) में पेश कर दिये जायेंगे। हंसमुख भाई दवे के हवाले से सभी बुर्जुआ अखबारों में प्रमुखता से प्रधानमंत्री का यह आश्वासन छापा गया। लेकिन, दूसरे दिन सम्मेलन खत्म होने पर श्रम मंत्री सत्यनारायण जटिया ने अखबार वालों को यह बताया कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई आश्वासन प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है। यह खबर दूसरे दिन अधिकांश अखबारों में भीतर के पन्नों पर छपी, जिसपर अधिकांश लोगों का ध्यान भी नहीं गया। लोगों को प्रधानमंत्री का आश्वासन ही याद रहा।

दूसरे दिन अखबार वालों से बात करते हुए श्रममंत्री ने इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया कि श्रम कानूनों में संशोधन सम्बन्धी विधेयक आगामी संसद-सत्र में भी पेश किया जा सकता है। सम्मेलन के अन्य फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए सत्यनारायण जटिया ने बताया कि श्रम कानूनों में संशोधनों पर आम राय बनाने के लिए और निजीकरण-उदारीकरण की प्रक्रिया से घरेलू उद्योगों पर पड़ने वाले असर का मूल्यांकन करने के लिए मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जायेगा और

(पेज 10 पर जारी)

जापानी डकैतों के लूट का एक ही तरीका कम मज़दूरों से ज्यादा मुनाफा

मुकुल

भूमण्डलीकरण के वर्तमान दौर में उदारीकृत अर्थव्यवस्था को लागू करने और भारत सहित तीसरी दुनिया के तमाम देशों को बाज़ार के लिये खोलते जाने के बावजूद विश्व पूंजीवाद आर्थिक मंदी के दुश्चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहा है। दो वर्ष पूर्व सूचना तकनीक के क्षेत्र से शेयर बाजार में आये उछाल से फूला साम्राज्यवाद का गुब्बारा भी अब पिचकने लगा है। हालात ये हैं कि 'सुपर किंग' अमेरिका का शेयर बाजार नेस्डैक का सूचकांक जो मार्च, 2000' में 5000 पर था अप्रैल 2001' में धड़ाम से नीचे आकर 1680 पर पहुंच गया। यही हाल दुनिया के दूसरे विकसित औद्योगिक देशों का भी है।

पिछले कुछ वर्षों में कम्पनियों के विलय और इस क्रम में मज़दूरों की छंटनी विश्वपूंजीवादी तंत्र में रूटीन सा बन गया है। टेलीफोन क्षेत्र में अग्रणी स्वीडेन की एरिक्सन कम्पनी और जापान की सोनी कम्पनी भारी घाटे के कारण विलय की प्रक्रिया में है और एरिक्सन कम्पनी अपने 22 हजार कर्मचारियों को काम से निकालने की योजना बना रही है। संकट के मंडराते बादलों से विश्व साम्राज्यवादी मुल्कों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है और इसकी गाज वे मज़दूरों पर गिराते जा रहे हैं, जकड़बन्दी बढ़ा रहे हैं। इस रोल में जापानी साम्राज्यवादियों की अग्रणी भूमिका बन गयी है। यही नहीं, 19वीं सदी के क्लासिकीय पूंजीवाद के तर्ज पर डाकेजनी की पुनर्वापसी में भी जापानियों ने अग्रणी भूमिका निभाई है।

जापानी डाकुओं के तौर-तरीके

आइये देखें, जापानी लुटेरों के मेहनतकशों को निचोड़ने के तौर-तरीके क्या हैं?

मज़दूर आबादी को बाध्य करके उनकी श्रमशक्ति को सस्ती से सस्ती दरों पर खरीदने और अतिलाभ निचोड़ने में तथा उन्हें संगठित होने से रोकने अथवा उनकी संगठित शक्तियों को बिखराने में जापानी डाकुओं का कोई जोड़ नहीं है। इसने अपनी इस लुटेरी कार्यपद्धति से अमेरिकी डाकुओं को भी सिखाया है।

जापानी डाकुओं का सबसे अहम तरीका है आदमियों से रोबोट की तरह काम लेना। वे मशीनी उपकरणों की भांति मानव को भी उपकरण की ही तरह इस्तेमाल करते हैं। उनकी निगाहें हर पल इसी पर लगी होती हैं कि मज़दूरों के खून को ज्यादा से ज्यादा निचोड़कर कैसे मुनाफे और अति मुनाफे में बदला जाये। थोड़े से मज़दूरों को थोड़ी ज्यादा सुविधाएं देकर (सफेद कालर मज़दूर बनाकर) ज्यादा से ज्यादा काम मामूली दिहाड़ी पर कैजुअल या ठेके से करवाने पर ही इनका जोर रहता है।

(पेज 10 पर जारी)

भीतर के पन्नों पर

1. तराई का एक और कारखाना तालेबंदी का शिकार – पृ. 3
2. चीनी क्रांति की सचित्र कथा – पृ. 6-9
3. मुर्गा और दारू के जश्न के बीच मज़दूर रहनुमाई का ढकोसला– पृ. 12
4. रंगे सियारों, बगुलाभगतों और ज़हरीले सांपों का जमावड़ा है लोकमोर्चा – पृ. 12

बाल्को की हड़ताल वापसी : एक और विश्वासघात

बिगुल प्रतिनिधि

लखनऊ। भारत अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बाल्को) के मजदूरों-कर्मचारियों की हड़ताल बिना कुछ हासिल किये वापस लेकर देश की प्रमुख केन्द्रीय ट्रेडयूनियनों ने मज़दूर वर्ग के साथ विश्वासघात की जानी-पहचानी कहानी दुहराई है। सड़सठ दिनों तक चला मज़दूरों का शानदार संघर्ष, जो निजीकरण के खिलाफ संघर्ष का एक प्रतीक माना जा रहा था, अब देश के मज़दूर आन्दोलन के इतिहास में विश्वासघात का एक ऐसा प्रतीक बन गया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।

पिछली आठ मई को 'बाल्को बचाओ संयुक्त अभियान समिति' के नेताओं और स्टरलाइट कम्पनी (इसी कम्पनी को बाल्को के 51 प्रतिशत शेयर कौड़ियों के मोल केन्द्र सरकार ने बेच दिये हैं) के बीच हुए समझौते में मज़दूरों की एक भी मांग नहीं मानी गयीं। लेकिन अभियान समिति के संयोजक बालेश्वर झा के अनुसार उनकी 25 में से 24 मांगें मान ली गयी हैं और "सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सम्मान तथा राष्ट्रहित के मद्देनजर" हड़ताल वापस ली गयी है। 25 सूत्री मांगपत्र का विस्तृत ब्यौरा तो अभी तक नहीं उपलब्ध हो पाया है, लेकिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि कोई भी महत्वपूर्ण मांग नहीं मानी गयी है।

स्टरलाइट कम्पनी के साथ वार्ता की मेज पर जाने का मतलब ही यही था कि निजीकरण का फैसला रद्द कराने की मांग को छोड़ दिया गया है। जबकि आन्दोलन की केन्द्रीय मांग ही यही थी। इसी कारण पहले आन्दोलन के नेता सिर्फ केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता करने पर अड़े हुए थे और स्टरलाइट के साथ किसी

(पेज 2 पर जारी)

बजा बिगुल मेहनतकश जाग, चिंगारी से लगेगी आग!

(पृष्ठ 1 से आगे)

बाल्को की हड़ताल वापसी

भी तरह की वार्ता से इन्कार करते चले आ रहे थे। ऐसे में स्टरलाइट के साथ वार्ता के लिए राजी होना ही आन्दोलन की प्रमुख केन्द्रीय मांग से पीछे हटना था। वह भी आन्दोलन के ऐसे मुकाम पर जब 18 मई को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी मज़दूरों-कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल पर जाने का मन बना लिया था। बाल्को के संघर्षरत मज़दूरों को देशभर से केवल नैतिक ही नहीं भौतिक मदद भी मिल रही थी। इससे उत्साहित होकर वे संघर्ष को और लम्बा खींचने के लिए तैयार थे।

संघर्ष की इस अनुकूल परिस्थिति में भी अभियान समिति के नेताओं द्वारा स्टरलाइट के साथ समझौते के लिए तैयार हो जाना सिर्फ यही बताता है कि वे यह लड़ाई किसी मजबूरी में लड़ रहे थे और उन्हें पीठ दिखाने का कोई ठोस बहाना नहीं मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह बहाना मुहैया करा दिया और उन्होंने न्यायपालिका के सम्मान और राष्ट्रहित की दुहाई देते हुए एक बेहद सम्भावनापूर्ण संघर्ष की पीठ में छुरा भोंक दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने देशी-विदेशी पूंजी के हितों की खुली तरफदारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस बार पहले से अधिक चतुराई से हड़ताल तोड़ने में अपनी परोक्ष भूमिका निभायी। डाक हड़ताल को तोड़ने में निभायी गयी प्रत्यक्ष भूमिका को लेकर बुर्जुआ मीडिया तक ने जो उंगलियां उठायी थी, शायद उससे सीखते हुए इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बारीक चाल खेली। ठीक मई दिवस के दिन बाल्को मामले की सुनवाई के दौरान स्टरलाइट के वकील की पेशकश पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने मज़दूरों से आठ मई तक यह जवाब देने के लिए कहा था कि अगर उन्हें दो महीने का एडवांस मिल जाये तो क्या वे काम पर वापस आने के लिए तैयार हैं। लेकिन नेताओं पर आन्दोलनरत आम मज़दूरों-कर्मचारियों का दबाव इतना जबर्दस्त था कि आठ मई को अपने जवाब में यूनियनों ने अदालत की पेशकश ठुकरा दी। इस जवाब पर खण्डपीठ की जो प्रतिक्रिया थी उससे साफ जाहिर है कि वह इन्कार सुनना नहीं चाहती थी। उसने पेशकश नामंजूर करने पर नाराजगी जतायी और कहा कि ऐसा करके कर्मचारियों ने उसके विश्वास को ठेस पहुंचायी है। अदालत को उम्मीद थी कि कर्मचारी काम पर वापस लौट आयेंगे। वे नहीं लौटे यह उनका फैसला है। अदालत उन्हें जबरन काम पर आने के लिए नहीं कह सकती। आठ मई की इस अदालती कार्रवाई के बाद अचानक आन्दोलन के नेताओं को अदालत के सम्मान और राष्ट्रहित की इतनी चिन्ता हो उठी कि उन्होंने स्टरलाइट के साथ वार्ता को मंजूरी दे दी।

यह समूचा घटनाक्रम सिर्फ इस बात का गवाह है कि 'बाल्को बचाओ संयुक्त अभियान समिति' में शामिल सभी यूनियनें सिर्फ अपनी-अपनी सियासी गोटी लाल करने के लिए और बाल्को के मज़दूरों-कर्मचारियों के दबाव में ही मजबूरी में आन्दोलन में शामिल थीं। मज़दूरों-कर्मचारियों के भविष्य के बारे में वे कतई चिन्तित नहीं थे। न ही निजीकरण के खिलाफ़ कोई फैसलाकुन लड़ाई लड़ने की उनकी मंशा थी।

'बाल्को बचाओ संयुक्त अभियान समिति' में शामिल पांच प्रमुख केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों – कांग्रेस से जुड़ी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक), भाजपा से सम्बद्ध भारतीय मज़दूर संघ, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई.) से जुड़ी आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से जुड़ी सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) और समता पार्टी से सम्बद्ध हिन्द मज़दूर सभा – ने बाल्को सौदे के खिलाफ संघर्ष में सिर्फ इसलिए अगुवाई की जिससे वे इस मुद्दे के बहाने अपनी-अपनी सियासी गोटियां लाल कर सकें। दरअसल, ये यूनियनें जीतने के लिए लड़ ही नहीं रही थीं। अगर यह उनका मकसद होता तो सड़सठ दिनों तक चली इस शानदार हड़ताल के पक्ष में देशव्यापी जनान्दोलन खड़ा किया जा सकता था। जब ये सभी पार्टियां नीतिगत रूप में निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों की हिमायती हैं तो उनकी ट्रेड यूनियनें अगर किसी एक कारखाने के निजीकरण का विरोध कर रही है तो जाहिर है कि इसका सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है – इतनी कवायद करते रहो जितनी मजबूरी हो और जिससे ट्रेड यूनियन दुकानदारी चलती रहे। यह कवायद इसलिए जरूरी हो गयी थी क्योंकि बाल्को में कार्यरत आम मज़दूर-कर्मचारी के ही नहीं वरन समूचे बाल्को नगर की महिलाएं और आसपास की आदिवासी आबादी के भीतर बाल्को सौदे के खिलाफ जबर्दस्त आक्रोश था। आन्दोलन का नेतृत्व कर रही सभी ताकतों ने अपने-अपने ढंग से इस आक्रोश का अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। अजित जोगी ने अपने ढंग से किया, बी.एम.एस. ने अपने ढंग से और सीटू-एटक ने अपने ढंग से। सत्ताधारी पार्टी से जुड़ी होने के बावजूद बी.एम.एस. ने मज़दूरों के पक्ष में खड़े होकर मज़दूर समर्थक चेहरा बनाने की कोशिश की तो सीटू-एटक को यह दावा करने का एक प्रमाण हासिल हो गया कि वे सिर्फ आर्थिक ही नहीं राजनीतिक लड़ाइयां भी लड़ती हैं। लेकिन इस कवायद के बाद जिस तरह सबने मिलकर स्टरलाइट से समझौता किया उसने सचेत मज़दूरों के सामने अपना असली चरित्र खुद

(पेज 3 पर जारी)

आपस की बात

बिगुल लगातार मिल रहा है।

नये श्रम-कानूनों – एकताबद्ध संघर्ष, पार्टी की बुनियादी समझदारी, जनमुक्ति की अमरगाथा तथा लेनिन के जन्मदिन पर लेख अच्छे लगे तथा समझदारी और विकसित हुई। सभी संघर्षरत साथियों को लाल सलाम।

का. महेश "महर्षि"
श्री गंगानगर (राजस्थान)

बिगुल लगातार और बेहतर होता जा रहा है। कारखानों पर रपटें, आन्दोलन की खबरें और राजनीतिक शिक्षा की सामग्री एक साथ पढ़ने को मिल रही है। मई दिवस विशेषांक पर सामग्री काफी विचारोत्तेजक और शिक्षित करने वाला है। मई दिवस पर लेनिन व स्तालिन के पर्चे हमारे इतिहास की धरोहर हैं। इसे बार-बार प्रकाशित होना चाहिए। हावर्ड फास्ट का लेख न केवल इतिहास से परिचित कराता है बल्कि प्रेरणादायी भी है। महत्वपूर्ण अवसरों पर 'बिगुल' द्वारा प्रकाशित विशेषांकों की आज महती आवश्यकता है।

सुरेश कुमार
गोरखपुर

बिगुल का स्तर लगातार अच्छा होता जा रहा है। जल्दी ही दक्षिणी राजस्थान के भूखे-नंगे, अकाल से पीड़ित आदिवासियों पर रिपोर्ट भेजना शुरू करूंगा।

लक्ष्मी नारायण मिश्र
उदयपुर (राजस्थान)

विकल्प

साफ-साफ और खुलेआम
क्यों नहीं कहते तुम
वह जो तुमने मेरे कान में कहा

तुम्हें बेइज्जती का डर है
वाजिब भी है
सुरक्षा के नाम पर
खूंखार अपराधी
और बलशाली – मूर्ख भी हैं
उसकी सेवा में अनेकों

उसका अतीत
उसका इतिहास भी कोई
कम खौफनाक तो नहीं
जरूरी था अब इस वक्त
बाहें थाम लेना राजनीति की
सुदृढ़ करने के लिए
अपनी सामाजिक स्थिति,
मिल चुकी है – क्लीन चिट

तंत्र व्यवस्था न्यायालय से
अब निरंतर जारी कर रहा है वह
सच्चरित्रता के ढेरों प्रमाण-पत्र
उन्हें जो अपराधी हैं या नहीं हैं
हथियार-धारी हैं या निहत्थे हैं
सभी तो उसका मुंह जोह रहे हैं

वाजिब है तुम्हारा भय
अकूत धन है उसके पास
काला सोना
दरअसल, काला पैसा, पीला सोना
नहीं तुम इस पर कोई
प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते
इस काली कमाई के वास्ते
आयकर विभाग और खोजी दस्ते,
कुत्ते
सब उसी के अधीन हैं
यह जानते हुए भी कि वह
कितना सबल है
तुम फुसफुसा रहे हो
मेरे कान में

अभी देखते ही उसका कोई चमचा
घर के अंदर दुबक रहोगे
किसी कोने में
या, मुठभेड़ होने पर सामने
बांधोगे उसकी तारीफों के पुल
भींग जाओगे उसकी नर्म सहृदयता
से
और तब चुपके से खिसक जाओगे
किसी संकरी गली में

सच है उस दैत्य से तुम
लड़ भी कैसे सकते हो अकेले और
निहत्थे
तुम्हारा साथ देने को भी कोई अभी
तैयार नहीं
लोभ-लाभ का गणित जो
उसके पास है
ऐसी स्थिति में दो ही विकल्प हे
या तो जोर से चिल्लाओ
या फिर भाग जाओ घने जंगल में

शैलेन्द्र चौहान
नागपुर (महाराष्ट्र)

बिगुल का स्वरूप, उद्देश्य और ज़िम्मेदारियां

1. 'बिगुल' व्यापक मेहनतकश आबादी के बीच क्रान्तिकारी राज़नीतिक शिक्षक और प्रचारक का काम करेगा। यह मजदूरों के बीच क्रान्तिकारी वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार करेगा और सच्ची सर्वहारा संस्कृति का प्रचार करेगा। यह दुनिया की क्रान्तियों के इतिहास और शिक्षाओं से, अपने देश के वर्ग संघर्षों और मजदूर आंदोलन के इतिहास और सबक से मजदूर वर्ग को परिचित करायेगा तथा तमाम पूंजीवादी अफवाहों-कुप्रचारों का भण्डाफोड़ करेगा।

2. 'बिगुल' देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक स्थितियों के सही विश्लेषण से मजदूर वर्ग को शिक्षित करने का काम करेगा।

3. 'बिगुल' भारतीय क्रान्ति के स्वरूप, रास्ते और समस्याओं के बारे में क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के बीच जारी बहसों को नियमित रूप से छापेगा और स्वयं ऐसी बहसें लगातार चलायेगा ताकि मजदूरों की राजनीतिक शिक्षा हो तथा वे सही लाइन की सोच-समझ से लैस होकर क्रान्तिकारी पार्टी के बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें और व्यवहार में सही लाइन के सत्यापन का आधार तैयार हो।

4. 'बिगुल' मजदूर वर्ग के बीच लगातार राजनीतिक प्रचार और शिक्षा की कार्रवाई चलाते हुए सर्वहारा क्रान्ति के ऐतिहासिक मिशन से उसे परिचित करायेगा, उसे आर्थिक संघर्षों के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के लिए भी लड़ना सिखायेगा, दुअन्नी-चवन्नीवादी भूजाछोर "कम्युनिस्टों" और पूंजीवादी पार्टियों के दुमछल्ले या व्यक्तिवादी-अराजकतावादी ट्रेडयूनियनबाजों से आगाह करते हुए उसे हर तरह के अर्थवाद और सुधारवाद से लड़ना सिखायेगा तथा उसे सच्ची क्रान्तिकारी चेतना से लैस करेगा। यह सर्वहारा की कतारों से क्रान्तिकारी धरती के काम में सहयोगी बनेगा।

5. 'बिगुल' मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी शिक्षक, प्रचारक और आह्वानकर्ता के अतिरिक्त क्रान्तिकारी संगठनकर्ता और आन्दोलनकर्ता की भी भूमिका निभायेगा।

बिगुल यहां से प्राप्त करें

● शहीद पुस्तकालय, जनगण होम्यो सेवा सदन, **मर्यादपुर**, मऊ ● मौर्या बुक स्टाल, सआदतपुरा (निकट रोडवेज), मऊनाथभंजन, **मऊ** ● जनचेतना, जाफरा बाजार, **गोरखपुर**
● विजय इन्फारमेशन सेन्टर, कचहरी बस स्टेशन, **गोरखपुर** ● विश्वनाथ मिश्र, नेशनल पी.जी. कालेज, **बड़हलगंज**, गोरखपुर
● जनचेतना, डी 64, निरालानगर **लखनऊ** ● जनचेतना स्टाल, काफी हाउस के पास, हजरतगंज, **लखनऊ**, (शाम 5 से 8-30) ● राहुल फाउण्डेशन, 69, बाबा का पुरवा, पेपरमिल रोड, निशातगंज, **लखनऊ** ● विमल कुमार, बुक स्टाल, निकट नीलगिरि काम्प्लेक्स, ए ब्लाक, इंदिरानगर, **लखनऊ** ● मदन पाल, दुकान नं. 28, नयी सब्जी मंडी, पुराने कपड़े का मार्केट, **रुद्रपुर** (ऊधम सिंह नगर) ● रामपाल सिंह, भारतीय जीवन बीमा निगम, आवास विकास, **रुद्रपुर** (ऊधमसिंहनगर) ● रवीन्द्र कुमार, भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा कार्यालय, पन्तनगर ● प्रोग्रेसिव बुक सेंटर, विश्वनाथ मंदिर गेट, बी.एच.यू. **वाराणसी** ● राजीव वर्मा द्वारा डा. जे.पी. वर्मा, बी. पी. 82, पटेलनगर, **मुगलसराय**, वाराणसी ● राजेन्द्र प्रसाद, रेणु मेडिकल की गली, मुख्य सड़क, **रेणुकूट**, सोनभद्र ● सत्यम वर्मा, 81, समाचार अपार्टमेंट, मयूर विहार एक, **नई दिल्ली** ● ललित सती, एल.आई.सी., **फैज रोड शाख**, **दिल्ली** ● नई किरण पुस्तक भंडार, एफ 56, हरकेश नगर, ओखला, नई दिल्ली ● पंकज कुमार, 256, मॉडल टाउन, सोनीपत, हरियाणा ● डी. के. सचान, कृषि विज्ञान केंद्र, विकास भवन, नई कलक्ट्रेट, **गाजियाबाद** ● सुनील कुमार सिंह, सेक्टर 12 बी, 3150, बोकारो इस्पातनगर, **बोकारो** ● गणपतलाल, ग्राम काजी रसूलपुर, पो. तेघड़ा, **बेगूसराय** ● पीपुल्स बुक हाउस, पटना कालेज के सामने, **पटना** ● समकालीन प्रकाशन (प्रा.) लि. पुस्तक बिक्री केन्द्र, आजाद मार्केट, पीरमुहानी, **पटना** ● विमर्श, 22, स्वास्तिक काम्प्लेक्स, रसल चौक, **जबलपुर** ● नरभिन्दर सिंह, द्वारा डा. सुखदेव हुन्दल, ग्रा/पो. **सन्तनगर**, जिला सिरसा ● पंकज, प्लाट नं. 33, सैक्टर 15, सोनीपत (हरियाणा) ● सुखविंदर द्वारा कौ. दशरथ लाल, मकान नं. 14, लेबर कॉलोनी, गिल रोड, लुधियाना (पंजाब) ● राकेश गोरखा, सरस्वती पुस्तक मंदिर, प्रधान नगर, सिलीगुड़ी, **दार्जीलिंग** ● बुक मार्क, 6, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, **कलकत्ता** ● शर्मा बुक स्टाल, थाना रोड, चरली, तिनसुकिया **नेपाल** ● विश्व नेपाली पुस्तक सदन, श्रवनपथ, बुटवल, रूपनदेई, नेपाल ● विशाल पुस्तक सदन, बिजुवार बाजार, प्यूठान राप्ती अंचल ● विशाल पुस्तक पसल, अस्पताल लाइन, बुटवल, लुम्बिनी, नेपाल ● लक्ष्मी नारायण मिश्र, 853, हिरन नगरी, सेक्टर4, फूलनगर, उदयपुर (राज.)

तराई का एक और कारखाना तालाबन्दी का शिकार:

मालिकों की धोखाधड़ी से सलोराकर्मी आन्दोलन के लिये बाध्य

बिगुल संवाददाता

काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)। 4 मई (छल-कपट, धोखाधड़ी की एक और कहानी रची गयी, यहां श्वेत-श्याम टेलीविजन बनाने वाले एक महत्वपूर्ण कारखाने 'सलोरा इण्टरनेशनल लिमिटेड' में। वही कहानी जो तराई से लेकर पूरे मुल्क में उदारीकरण के दौर की हकीकत बनी हुई है। सलोरा मालिक बड़े ही सुनियोजित तरीके से विगत 10 मई को कारखाने में तालाबन्दी करके रफूचक्कर हो गये। एक झटके में सड़क पर धकेल दिये गये यहां के मज़दूर अब जीवन-मरण का संघर्ष कर रहे हैं।

इस कारखाने को बन्द करने की साजिश प्रबन्धकों ने कुछ माह पूर्व ही रचनी शुरू कर दी थी। मज़दूरों को इसकी भनक तक नहीं लग पायी थी। होली के बाद कारखाने से कुछ कंपोनेंट – जिग टेस्टर व अन्य कई उपकरण रात में ट्रकों में भरकर प्रबन्धकों ने अपने नोएडा व दिल्ली इकाइयों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। इस माह के शुरू में (3 से 6 मई) प्रबन्धकों ने विद्युत आपूर्ति व टेलीविजन आपूर्ति आदेश न होने के बहाने कर्मचारियों की छुट्टी कर दी थी। 7 मई को कारखाना खुलने पर बकायता वेतन का भुगतान हुआ। इसी दिन महाप्रबन्धक आर.एम.सेठ ने श्रमिकों को दिग्भ्रमित करते हुए कहा कि, कारखाने के अस्तित्व को बचाने की कोशिश पर गंभीरता से विचार चल रहा है ... फैक्ट्री बन्दी या अन्यत्र स्थानान्तरण का कोई आदेश प्राप्त नहीं है। शाम को कारखाने में एक नोटिस चस्पा हो गया – आपूर्ति आदेश न होने से 8 मई को अवकाश रहेगा (9 को साप्ताहिक अवकाश था) कारखाना पुन: 10 मई को खुलेगा।।

जाति-क्षेत्र व अलग-अलग कारखाने के संकीर्ण बंटवारे को तोड़ना होगा! क्षेत्रीय पैमाने के मज़दूर आन्दोलन को संगठित करना होगा!!

10 मई को जब सलोराकर्मी कारखाना पहुंचे तो वहां कहानी खत्म हो चुकी थी। कारखाने में मालिकों का ताला लग चुका था। वहां एक नोटिस लगी थी –घाटे के कारण कारखाना बन्द कर दिया गया है, ... आपका हिसाब चेक द्वारा आपके घर पर भेज दिया जायेगा।

इस घटना से हतप्रभ श्रमिकों में अफरा-तफरी मच गयी। संकट की इस घड़ी में यहां के मज़दूरों ने तत्काल आन्दोलन की राह पकड़ी। उन्होंने जुलूस निकालकर उपजिलाधिकारी, काशीपुर को ज्ञापन दिया, श्रम कार्यालयों में भागदौड़ शुरू की और कारखाना स्थल पर वे धरने पर बैठ गये।

उल्लेखनीय है कि इस कारखाने में कुल 109 स्थायी श्रमिक (स्टाफ सहित) कार्यरत रहे हैं जिनमें 72 महिलाएं हैं। इसके अतिरिक्त 40-50 के बीच ठेका श्रमिक कार्य करते रहे हैं। वर्तमान समय में 11 अप्रेंटिस प्रशिक्षु भी कार्यरत थे। इस घटना ने इन सबके भविष्य पर ताला लगा दिया। दिसम्बर' 86 में स्थापित इस कारखाने में मालिकों ने यूनियन तक नहीं बनने दी थी। यही नहीं, 1970 रु. से 2700 रु. के मामूली तनख्वाह पर यहां के स्थायी श्रमिक गुजर-बसर करते रहे हैं। अभी कुछ माह पूर्व यहां के श्रमिकों ने यूनियन बनाने की पहल ली थी। लेकिन यह प्रक्रिया अभी आगे भी नहीं बढ़ पायी थी कि कारखाने में तालाबन्दी हो गयी। और अब यही पहलकारी टीम 'सलोरा बचाओ संघर्ष समिति' के रूप में बदल गयी है।

तराई के उर्वर क्षेत्र में टी.वी. बनाने का यह कारखाना उस वक्त लगा था जब क्षेत्र के विकास के नाम पर रेवड़ी की तरह सब्सिडियां बांटी जा रही थीं। उस वक्त देशी-विदेशी मुनाफाखोरों ने नये-नये उद्योग लगाने शुरू किये। क्षेत्र की जनता की जगह कारखानेदारों का विकास होता चला गया। वे एक कारखाने से कई और कारखाने खड़ी करते गये। खुद सलोरा मालिकों ने यहां से मुनाफा निचोड़कर दिल्ली-नोएडा क्षेत्र में दो और कारखाने स्थापित कर लिये हैं। और अब इस क्षेत्र को दुहने-निचोड़ने और सब्सिडियों को हड़पने के बाद ये तमाम कारखानेदार यहां से भाग रहे हैं।

श्रम कानूनों में हो रहे बदलाव और सरकार के मालिकों के पक्ष में खुलकर आ जाने से उनके हौसले और भी बुलन्द हो गये हैं।। अभी पिछले दिनों **नैना सेमी कण्डक्टर** (हल्दूचौड़, नैनीताल) के प्रबन्धकों ने ऐसे ही तालाबन्दी कर दी थी, लेकिन क्षेत्रीय जनदबाव के कारण उसे कारखाना खोलना पड़ा। **रामाविजन लि.** (किच्छा) में प्रत्येक माह 17-18 दिन 12-12 घण्टे हाड़तोड़ मेहनत से

कार्य करवाने के बाद 11-12दिन की अचानक छुट्टी कर दी जाती है और तरह-तरह की अफवाहें फैलायी जाती रहती हैं जिससे लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। जापानी कारखाना **होण्डा पावर प्रोडक्ट्स लि.** में भी प्रबन्धतन्त्र कुछ मशीनें शिफ्ट कर चुका है और कई के शिफ्ट करने की योजनाएं बना चुका है। चूंकि यहां एक जुझारू यूनियन है और लोगों में एकता है (जिसे तोड़ने के लिए प्रबन्धतंत्र लगातार प्रयासरत रहा है) इसलिये प्रबन्धक वर्ग यहां लम्बी रणनीति पर कार्य कर रहा है।

उधर तराई के मज़दूर भी मालिकों के इन षडयंत्रों को भांपने लगे हैं और अपनी वर्गीय एकता बनाने के प्रयासों में जुट गये हैं। तमाम जागरुक मज़दूरों की निगाहें पूंजीपतियों की साजिशों पर टिकी हुई हैं। यही कारण है कि जैसे ही सलोरा बन्दी की खबर क्षेत्र में फैली, तमाम संगठनों ने उसे समर्थन देना शुरू कर दिया। बगल के **सूर्या श्रमिक संगठन** ने आन्दोलन को अपना समर्थन दिया। रुद्रपुर के **होण्डा पावर प्रोडक्ट्स** में यूनियन ने तत्काल गेट मीटिंग करके तालाबन्दी पर क्षोभ व्यक्त करते हुए वहां के आन्दोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया। दूसरी तरफ, **श्रीराम होण्डा श्रमिक संगठन, आनन्द निशिकावा श्रमिक संगठन, बैंक कर्मचारी मंच, बीमा कर्मचारी संघ और बिगुल मज़दूर दस्ता** ने संयुक्त बैठक करके इस अवैधानिक तालाबन्दी को तत्काल खोलने की मांग करते हुए सलोराकर्मियों के आन्दोलन को अपना समर्थन व्यक्त किया और क्षेत्र की मेहनतकश जनता से इस न्यायपूर्ण आन्दोलन के पक्ष में एकजुट होने का आह्वान किया।

जहां तक सलोरा का सवाल है, तो यहां के मालिकों ने घाटे को कारखाना बन्दी के लिए कवच के रूप में इस्तेमाल किया है। पहली बात तो यह है कि इस कारखाने में वर्तमान समय में कोई घाटा नहीं था। पिछले वर्ष के वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में प्रबन्ध निदेशक आर.पी.खेतान द्वारा इस कारखाने को 10 करोड़ 25 लाख 44 हजार के फायदे में दिखलाया गया है। दूसरे, यदि कम्पनी में कोई संकट था तो उसने धोखे से इसे बन्द क्यों किया? उसने श्रमिकों से बातचीत करना भी उचित नहीं समझा। यहां तक कि 90 दिन की पूर्व नोटिस देने की औपचारिकता भी इसने नहीं निभाई।

यह एक कटु सत्य है कि सस्ते रंगीन टी.वी. के वर्तमान दौर में श्वेत-श्याम टी.वी. का बाज़ार लगभग समाप्त होता जा रहा है। पिछले 15 वर्षों में इस कारखाने से मालिकों को जितना मुनाफा निचोड़ना था, निचोड़ चुका है। इस मुनाफे से वह और जयादा मुनाफे वाला उद्योग लगायेगा और नयी सब्सिडियां हड़पेगा। सभी पूंजीवादी लुटेरों की तरह इस लुटेरे ने भी मज़दूरों के श्रम को जितना टकसाल में ढाल सकता था, ढाल लिया और फिर खोटे सिक्के की तरह इन्हें सड़क पर फेंक दिया। इन पूंजीपतियों का वश चले तो वे मज़दूरों की हड्डियों का सुरमा बनाकर बाज़ार में बेंच दें।

आज का दौर नये-नये आधुनिक तकनीकों से कम से कम श्रम शक्ति की बदौलत ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निचोड़ने का है। इसीलिये वे 'हायर एण्ड फायर' (जब चाहो भर्ती करो जब चाहो निकाल दो यानी मज़दूरों को उपकरण की भॅति इस्तेमाल करके फेंक देने की राह में कोई कानूनी अवरोध भी न पैदा हो) की श्रम-नीति लागू कर रहे हैं।

मज़दूर आबादी को इन स्थितियों को समझने और इसके खिलाफ तैयार रहने की जरूरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में सलोरा का संकट पूरी मज़दूर आबादी का संकट है। और इसीलिये यह आन्दोलन पूरी मज़दूर आबादी का आन्दोलन है।

आज मज़दूरों के ज्यादा से ज्यादा दोहन के लिये देश और पूरी दुनिया के पूंजीपतियों ने नापाक एकता कायम कर रखी है। उनके 'चैम्बर' ज्यादा सक्रिय हैं और उनके साथ सरकार से लेकर पुलिस-फौज-न्यायालय तक मुस्तैदी से खड़े हैं। जबकि बहुसंख्यक मेहनतकश जनता क्षेत्र-जाति के नाम पर, ठेका-स्थायी के नाम पर, अलग-अलग कारखानों-विभागों के नाम पर, संगठित-असंगठित के नाम पर अथवा सरकारी-गैरसरकारी के नाम पर बंटी हुई है। आज मज़दूर आबादी को इन संकीर्ण बंटवारों को तोड़ना ही होगा। यही वक्त का तकाजा है। और तभी इन लुटेरों के नापाक इरादों को ध्वस्त किया जा सकता है।

आन्दोलनरत सलोराकर्मियों को अपने आन्दोलन को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिये इलाकाई पैमाने पर व्यापक मज़दूर एकता बनाते हुए सूझ-बूझ भरे कदम उठाने होंगे। उन्हें चुनावी मदारियों से सावधान रहना होगा। सहयोग-समर्थन व सुझाव तो सबसे लिया जाना चाहिए, लेकिन योजनाएं हवाई नहीं जमीनी बननी चाहिए। आन्दोलन तो मज़दूरों के लिये एक पाठशाला है जो बहुत कुछ सीखने का मौका देता है। और यह भी सच है कि बगैर लड़े कुछ भी नहीं मिलता।

(पृष्ठ 2 से आगे)

बाल्को की हड़ताल वापसी

ही नंगा करके रख दिया।

इसके बावजूद आन्दोलन के नेता हद दर्जे की बेहयाई के साथ यह बयान दे रहे हैं कि उन्होंने 25 में से 24 मांगें मनवा ली हैं और निजीकरण के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। जबकि समझौते में स्टरलाइट के मालिकान ने सिर्फ एक ठोस आश्वासन दिया है कि हड़ताली मज़दूरों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले लिये जायेंगे। हड़ताल की अवधि का वेतन उसने अन्तरिम भुगतान के रूप में देना स्वीकार किया है। यह वेतन कार्य अवधि मानकर दिया जायेगा या इसे भविष्य में वेतन में समायोजित किया जायेगा। इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना है। स्टरलाइट के मालिकान ने हालांकि यह आश्वासन दिया है कि किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जायेगी, लेकिन इस तरह के आश्वासनों पर अमल कितना होता है, निजी कम्पनियों के कामकाज से परिचित हर आदमी बखूबी जानता है। बाल्को के पश्चिम बंगाल स्थित संयत्र या स्टरलाइट के मालिकाने वाली चेन्नई स्थित कम्पनी माल्को में तबादले पर सिर्फ एक साल तक रोक लगाने के लिए मैनेजमेंट राजी हुआ है। मज़दूरों की एक प्रमुख मांग यह थी कि प्रति मज़दूर 25 लाख रुपये की दर से गारंटी जमा की जाये; लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। जाहिर है कि कोई भी प्रमुख मांग बिना शर्त नहीं मानी गयी है।

जिन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है उनके बारे में स्टरलाइट मैनेजमेंट पूरी तरह आश्वस्त है कि वे उसके पक्ष में होंगे। निजीकरण-उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के रवैये को देखते हुए स्टरलाइट मालिकान का यह इत्मीनान अनायास नहीं है। निजीकरण के मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इस कानूनी आधार पर फैसला सुनाना है कि आदिवासियों की जमीन निजी कम्पनियों को बेची जा सकती है या नहीं।

कुल मिलाकर बाल्को के मज़दूरों को सड़सठ दिनों की लम्बी लड़ाई में एक बहुत बड़ा सिफर ही हासिल हुआ है। एक बार फिर ट्रेड यूनियन नेताओं की गद्दारी से एक शानदार संघर्ष को एक अभूतपूर्व पराजय का सामना करना पड़ा है। वैसी ही पराजय जैसी पिछली डाक हड़ताल या निजीकरण के खिलाफ बीमा आदि अन्य सेक्टरों में चली लड़ाइयों को मिली है। इस पराजय ने एक बार फिर मज़दूरों के सामने और अधिक तीखेपन के साथ उन बेशकीमती सबकों की याद दिलायी है जो सबक पिछली पराजयों ने सिखाये थे। लेकिन, यह भी इतिहास का एक सबक है कि मज़दूर वर्ग अपनी लड़ाइयों के दौरान अपनी जीतों से अधिक हारों से सीखता रहा है। निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ संघर्षों में पराजयों का यह सिलसिला मज़दूर वर्ग को यह सिखाता चल रहा है कि यह सिलसिला तभी रुकेगा जब वह चुनावी पार्टियों की पिछलग्गू ट्रेडयूनियनों से छुटकारा पायेगा और अपना नया क्रान्तिकारी नेतृत्व पैदा करेगा। पराजयों के सिलसिले को विजय के अभियानों में केवल तभी बदला जा सकता है।

मज़दूर वर्ग का यह नया क्रान्तिकारी नेतृत्व ही मज़दूर आन्दोलन को एक क्रान्तिकारी परिप्रेक्ष्य दे सकता है। केवल यही नेतृत्व अलग-अलग कारखानों, अलग-अलग सेक्टरों की लड़ाइयों को एक लड़ी में पिरोते हुए और समूची मेहनतकश जनता का नेतृत्व करते हुए पूंजी की समूची सत्ता के खिलाफ संघर्ष की दिशा में और मज़दूर वर्ग के ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने की दिशा में ले जा सकता है। लेकिन यह नेतृत्व अपने आप नहीं पैदा होगा। इसे नियति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यह केवल तभी होगा जब सभी वर्ग सचेत मज़दूर साहस के साथ आगे आयेंगे और अपने नये-नये संगी-साथी तैयार करेंगे। यह जिम्मेदारी उन्हें उठानी ही होगी।

बिगुल पोस्टर श्रृंखला के तहत प्राप्त करें दो आकर्षक पोस्टर

कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर

बिगुल पोस्टर -1

महान पेरिस कम्यून की 128वीं जयन्ती (18 मार्च) के अवसर पर

बिगुल पोस्टर -2

प्राप्ति स्थान

जनचेतना

डी-68, निराला नगर, लखनऊ-226 020

फोन : 788932

कम्युनिज्म सर्वहारा वर्ग का महान आदर्श है!

पार्टी का संविधान कहता है: "चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का बुनियादी कार्यक्रम बुर्जुआ वर्ग और दूसरे सभी शोषक वर्गों को पूरी तरह उखाड़ फेंकना, बुर्जआ वर्ग के अधिनायकत्व की जगह सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना और पूंजीवाद पर समाजवाद की विजय है। पार्टी का अन्तिम उद्देश्य कम्युनिज्म की प्राप्ति है।" हमें, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को, पार्टी के बुनियादी कार्यक्रम और अन्तिम लक्ष्य को अच्छी तरह से समझना चाहिए और कम्युनिज्म की प्राप्ति के लिए जान लड़ाकर संघर्ष करना चाहिए।

अध्यक्ष माओ बताते हैं: "कम्युनिज्म एक ही साथ सर्वहारा विचारधारा की एक सम्पूर्ण व्यवस्था और एक नई सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी भी दूसरी विचारधारा या सामाजिक व्यवस्था से अलग है और मानव इतिहास की सबसे सम्पूर्ण, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी और तर्कसंगत व्यवस्था है।" (माओ त्से-तुङ, नवजनवाद के बारे में)

कम्युनिस्ट समाज पर ये विशेषण क्यों लागू होते हैं? जवाब यह है:

कम्युनिस्ट समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें वर्गों और वर्ग विभेदों का समूल नाश हो चुका होता है। कम्युनिज्म के अंतर्गत सभी शोषक वर्गों व वर्ग-विभेदों के साथ ही साथ मज़दूरों और किसानों के बीच, शहर और गांव के बीच तथा शारीरिक और बौद्धिक श्रम के बीच के अंतर समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही उत्पादन के साधन एक केन्द्रीकृत कम्युनिस्ट स्वामित्व के अधीन हो जाते हैं।

कम्युनिस्ट समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें पूरी आबादी कम्युनिस्ट विचारधारात्मक चेतना और उच्च नैतिक गुणों से लैस होती है। कम्युनिज्म के अन्तर्गत, बुर्जुआ विचारधारा और स्वार्थी सोच को उखाड़ फेंकने के बाद, इंसान एक उन्नत कम्युनिस्ट चेतना और उच्च नैतिक गुणों के साथ, सचेतन तौर पर बाहरी दुनिया के साथ ही साथ अपने आन्तरिक जगत को बदलने के लिए मार्क्सवादी विश्व दृष्टिकाण का इस्तेमाल करेगा।

कम्युनिस्ट समाज एक ऐसा समाज होगा जिसमें सभी लोग सचेतन तौर पर और पूरे जोशोखरोश के साथ काम करेंगे। कम्युनिज्म के अन्तर्गत श्रम करना आदमी के जीवन की जरूरत बन जायेगा।

कम्युनिस्ट समाज एक ऐसा समाज होगा जिसमें सामाजिक सम्पदा अत्यधिक प्रचुर मात्रा में होगी। कम्युनिज्म के अन्तर्गत शोषक वर्गों और शोषण की व्यवस्थाओं का उन्मूलन उत्पादक शक्तियों की मुक्ति के लिए एक प्रशस्त मार्ग खोल देगा, जिनका भारी पैमाने पर विकास होगा और वे प्रचुर मात्रा में सामाजिक सम्पदा का उत्पादन करने में सक्षम हो जायेंगी, जिससे आदमी के जीने का स्तर बड़े पैमाने पर ऊपर उठ पायेगा।

कम्युनिस्ट समाज वह समाज होता है जो इस सिद्धान्त से परिचालित होता है, "प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार!" (मार्क्स: गोथा कार्यक्रम की आलोचना) कम्युनिज्म के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों का केन्द्रीकृत, कम्युनिस्ट सम्पत्ति में रूपान्तरण, सामाजिक सम्पदा की प्रचुरता और जनता की विचारधारात्मक चेतना के स्तरोन्नयन से यह सम्भव हो सकेगा कि हर व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार समाज के लिए काम करेगा और समाज के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार वस्तुओं का वितरण सम्भव होगा। इस समाज में अमीर और गरीब का फर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा।

कम्युनिस्ट समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें राज्यसत्ता विलुप्त हो चुकी होती है। कम्युनिज्म के अंतर्गत चूंकि वर्गों का लोप हो चुका होता है इसलिए साम्राज्यवाद, संशोधनवाद या प्रतिक्रियावाद का नामोनिशान मिट जायेगा। यह वर्ग-प्रभुत्व के औजार के रूप में राज्यसत्ता को बेमानी बना देगा। इसलिए राज्य स्वाभाविक प्रक्रिया में लुप्त हो जायेगा।

निचोड़ के तौर पर, कम्युनिज्म के अन्तर्गत, मानव-समाज, जैसा कि अध्यक्ष माओ कहते हैं, **"साम्राज्यवाद से मुक्त, पूंजीवाद से मुक्त और किसी भी दूसरी शोषण की व्यवस्था से मुक्त होगा।" (माओ त्से-तुङ: अल्बानियाई लेबर पार्टी की पांचवी कांग्रेस को शुभकामना संदेश: 25 अक्टूबर 1966, 'पीकिङ रिव्यू' के नवम्बर 1966 अंक में उद्धृत) जाहिरा तोर पर कम्युनिज्म के तहत वर्ग खत्म हो चुके होंगे, लेकिन अधि रचना एवं आर्थिक आधार के बीच और उत्पादन के सम्बन्धों एवं उत्पादक शक्तियों के बीच के अन्तरविरोध तब भी मौजूद रहेंगे। इन अन्तरविरोधों के प्रतिबिम्ब के रूप में वहां दो लाइनों के बीच, उन्नत और पिछड़ी चीजों के बीच, पुराने और नये के बीच तथा सही और गलत के बीच संघर्ष मौजूद रहेंगे। ये अन्तरविरोध, ये संघर्ष समाज के आगे के विकास को संवेग प्रदान करते हैं।**

कम्युनिस्ट समाज मानव समाज के विकास की तार्किक परिणति है। अध्यक्ष माओ ने कहा है: **"समाज में आने वाले बदलावों के जिम्मेदार मुख्य रूप से समाज के अन्दरूनी अन्तरविरोध होते हैं, अर्थात उत्पादक शक्तियों और उत्पादन के सम्बन्धों के बीच का अन्तरविरोध, वर्गों के बीच का अन्तरविरोध तथा पुराने और नये के बीच का अन्तरविरोध। इन अन्तरविरोधों का विकास ही समाज को आगे बढ़ाता है ..." (माओ त्से-तुङ, संकलित रचनाएं, खण्ड-1, "अन्तरविरोध के बारे में")।** ऐसे समाज में जहां शोषक वर्ग प्रभावी जगहों पर काबिज होते हैं, वहां उत्पादन के सम्बन्धों और उत्पादन शक्तियों के बीच, तथा अधिरचना और आर्थिक आधार के बीच के अन्तरविरोध अपने आपको वर्ग अन्तरविरोध और वर्ग संघर्ष के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। वर्ग अन्तरविरोधों और वर्ग संघर्ष का तेज होते जाना क्रान्ति या सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन की ओर ले जाता है। क्रान्ति में विकसित उत्पादक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला क्रान्तिकारी वर्ग स्वाभाविक तौर पर उत्पादक शक्तियों के विकास को रोके रखने वाले सड़ते हुए प्रतिक्रियावादी वर्ग पर जीत हासिल करता है। पुराने उत्पादन के सम्बन्धों और पुरानी अधि रचना को रूपान्तरित करने की प्रक्रिया में समाज आगे बढ़ता है। आदिम समाज के बाद आने वाले हर तरह के समाजों – दास समाज, सामन्ती समाज और पूंजीवादी समाज – में आदमी द्वारा आदमी का शोषण होता था। दास-स्वामियों के विरुद्ध दासों के, जमींदारों के विरुद्ध किसानों के और पूंजीपतियों के विरुद्ध मज़दूरों के वर्ग-संघर्ष ने ही समाज को आगे बढ़ाया है।

पूंजीवादी समाज वर्ग उत्पीड़न और शोषण पर आधारित आखिरी मानव समाज है। उत्पादन के सामाजिक चरित्र और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व के बीच का अन्तरविराध पूंजीवादी समाज का प्रधान अन्तरविरोध होता है। यह अन्तरविरोध सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के बीच के अन्तरविरोध और संघर्ष के रूप में प्रकट होता है।

पूंजीवादी समाज अपने ही अन्तरविरोधों को हल करने में पूरी तरह अक्षम होता है। केवल सर्वहारा वर्ग ही बल प्रयोग द्वारा बुर्जुआ वर्ग की सत्ता पलटकर और अपना प्रभुत्व स्थापित कर इन्हें हल करने में सक्षम होगा। बुर्जुआ वर्ग के अधिनायकत्व की जगह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व ले लेगा। पूंजीवादी निजी सम्पत्ति की जगह समाजवादी सामूहिक सम्पत्ति ले लेगी। यह सामाजिक विकास का अनिवार्य नियम है जिसका विराध कोई शक्ति नहीं कर सकती।

कम्युनिज्म निश्चित रूप से दुनिया में हर जगह विजयी होगा। पिछले सौ सालों से ज्यादा समय के दौरान, अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन मार्क्सवाद-लेनिनवाद के मार्गदर्शन और **कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र** द्वारा दिखायी गयी दिशा में, तेज विकास की प्रक्रिया से होकर गुजरा है। 1871 में, पेरिस कम्यून के बहादुर बेटे-बेटियों ने पहली बार सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापित करने की कोशिश की थी। 1917 में लेनिन के नेतृत्व में रूस में **अक्टूबर समाजवादी क्रान्ति ने जीत हासिल की। 1949 में चीनी जनता अध्यक्ष माओ के मार्गदर्शन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में लम्बे संघर्षों के बाद "तीन विशाल पर्वतों" को उखाड़ फेंकने और समाजवादी नये चीन की नींव रखने में कामयाब हुई। आज, देश आजादी चाहते हैं, राष्ट्र मुक्ति चाहते हैं और जनता क्रान्ति चाहती है – यह एक महान ऐतिहासिक प्रवृत्ति है जो पूरी दुनिया में विकसित हो रही है और जिसे कोई नहीं रोक सकता। कम्युनिज्म लोगों के दिलों में गहराई तक पैठ रहा है; सारी दुनिया की क्रान्तिकारी जनता में इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। जाहिरा तौर पर, कम्युनिज्म के हर जगह जीत हासिल करने से पहले, अनेक लम्बे और कठिन युद्ध सामने हैं जो जरूर लड़े जायेंगे।**

कम्युनिज्म पूरी दुनिया में संघर्षों के जरिये, एक यंत्रणादायी मार्ग से होकर आगे बढ़ रहा है। हालांकि विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन सोवियत संघ में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के अनुभव से होकर गुजरा है लेकिन यह एक अल्पकालिक परिघटना है। संशोधनवादी प्रभुत्व ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। सोवियत संघ का सर्वहारा और वहां की क्रान्तिकारी जनता निश्चित तौर पर ब्रेझनेव के गद्दार गुट को पराजित करने में और सर्वहारा अधि नायकत्व को मजबूती के साथ स्थापित करने में सफल होगी – इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि हमारी पार्टी के इतिहास में भी चेन तू-श्यू, वाङ मिङ और ल्यू शाओ-ची के गद्दार गुट तथा लिन प्याओ का पार्टी विरोधी गुट प्रकट हुए हैं, हालांकि क्रान्ति कई विचलनों से होकर गुजरी है, लेकिन अंततः इनमें से कोई भी क्रान्ति की अंतिम जीत को नहीं रोक सकता। इन कठोर और बारम्बार प्रकट होने वाले दो लाइनों के संघर्षों से हमारी पार्टी हमेशा से ज्यादा संगठित और ज्यादा गतिशील होकर उभरी है। संक्षेप में, कम्युनिज्म की प्राप्ति में, कार्यभार बेहद कठिन है, रास्ता यंत्रणादायी है, लेकिन भविष्य उज्जवल है। आगे आने वाले रास्ते पर हमें चाहे जितने चढ़ावों-उतारों और हारों का सामना करना पड़े, अगर हम मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुङ विचारधारा के मार्गदर्शन में चलते रहेंगे, अगर हम सभी देशों के मजदूरों से अपनी क्रान्तिकारी एकता को मजबूत बनाये रखेंगे, अगर हम क्रान्तिकारी स्पिरिट और जीत में अपने दृढ़ विश्वास को कायम रखेंगे, अगर हम उतार-चढ़ाव से न डिगें और दृढ़ता से संघर्ष करते रहें, तो निस्संदेह कम्युनिज्म पूरी दुनिया में जीत हासिल करेगा।

इतिहास में सभी अवसरवादियों ने वैज्ञानिक कम्युनिज्म के सिद्धान्त को झुठलाया है, छद्म-कम्युनिस्ट बकवास फैलायी है और कम्युनिज्म की क्रान्तिकारी दिशा को बदलने की उम्मीद में सर्वहारा वर्ग और क्रान्तिकारी जनता के दिलो-दिमाग में जहर भरने की कोशिश की है। सोवियत संशोधनवादी गद्दार गुट और ल्यू शाओ-ची और लिन प्याओ जैसे बदमाशों ने हमेशा "कम्युनिज्म" के झण्डे की आड़ में पूंजीवादी पुनर्स्थापना के लिए कदम उठाये हैं। ख्रुश्चेव के अनुसार कम्युनिज्म का अर्थ था "बढ़िया खाना, अच्छे कपड़े पहनना", हर आदमी का गुलाश (एक लजीज रूसी व्यंजन) खाने के काबिल होना। ल्यू शाओ-ची के लिए कम्युनिज्म का अर्थ था – "सजना-धजना, लिपस्टिक लगाना, रोजमर्रा की जिन्दगी के किस्से बघारना; जबकि लिन प्याओ के अनुसार कम्युनिज्म का मतलब था "सबका अमीर बनना, सभी का अच्छा जीवन जीना"। उन्होंने शोषक वर्गों के उन्मूलन के बारे में एक शब्द कहे बिना जनता की कम्युनिस्ट चेतना को ऊपर उठाने के सवाल पर चुप्पी साधे हुए और इस तरह कम्युनिज्म के असली अर्थ का ही अनर्थ करते हुए, 'खाओ-पियो-मस्त रहो' की बुर्जुआ सोच का व्यापक प्रचार किया। उनका "कम्युनिज्म" सिर्फ नाम का कम्युनिज्म था, लेकिन वह असल में था पूंजीवाद। यह इन नकली मार्क्सवादियों के कुरूप चेहरे और पूंजीवाद की पुनर्स्थापना करने के उनके आपराधिक षडयंत्र को उजागर कर देता है।

(अगले अंक में जारी)

विशेष सामग्री

(पांचवी किश्त)

अध्याय - 3

पार्टी की बुनियादी समझदारी

पार्टी का बुनियादी कार्यक्रम और अन्तिम लक्ष्य

एक क्रांतिकारी पार्टी के बिना मजदूर वर्ग क्रांति को कतई अंजाम नहीं दे सकता। लेनिन ने इस बात को बार-बार जोर देकर कहा था। स्तालिन और माओ ने भी बराबर इस बात पर जोर दिया और बीसवीं सदी की सभी सफल सर्वहारा क्रान्तियों ने भी इसे सत्यापित किया।

लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की क्रान्तिकारी पार्टी के सांगठनिक उसूलों का निर्धारण किया और इसी फौलादी सांचे में बोल्शेविक पार्टी को ढाला। चीन की पार्टी भी बोल्शेविक पार्टी की ही उत्तराधिकारी थी। सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान, समाजवादी समाज में वर्ग-संघर्ष का संचालन करते हुए माओ के नेतृत्व में चीन की पार्टी ने अन्य युगान्तरकारी सैद्धान्तिक उपलब्धियों के साथ-साथ लेनिनवादी सांगठनिक सिद्धान्तों को भी और आगे विकसित किया।

सोवियत संघ और चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के लिए बुर्जुआ तत्वों ने सबसे पहले यही जरूरी समझा कि सर्वहारा वर्ग की पार्टी का चरित्र बदल दिया जाये। हमारे देश में भी संसदीय रास्ते की अनुगामी नामधारी कम्युनिस्ट पार्टियां मौजूद हैं। भारतीय मजदूर क्रांति को सफल बनाने के लिए भारत में भी सर्वहारा वर्ग की एक सच्ची क्रान्तिकारी पार्टी खड़ी करने का काम सर्वोपरि है।

इसके लिए बेहद जरूरी है कि मजदूर वर्ग यह जाने कि असली और नकली कम्युनिस्ट पार्टी में क्या फर्क होता है और एक क्रान्तिकारी पार्टी कैसे खड़ी की जानी चाहिए।

इसी उद्देश्य से, फरवरी, 2001 अंक से हमने एक बेहद जरूरी किताब 'पार्टी की बुनियादी समझदारी' के अध्यायों का किश्तों में प्रकाशन शुरू किया है। इस अंक में पांचवी किश्त दी जा रही है। यह किताब सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान पार्टी-कतारों और युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए तैयार की गयी श्रृंखला की एक कड़ी थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की दसवीं कांग्रेस (1973) में पार्टी के गतिशील क्रान्तिकारी चरित्र को बनाये रखने के प्रश्न पर अहम सैद्धान्तिक चर्चा हुई थी, पार्टी का नया संविधान पारित किया गया था और संविधान पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। इसी नई रोशनी में यह पुस्तक एक सम्पादकमण्डल द्वारा तैयार की गयी थी। मार्च, 1974 में पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, शंघाई से इस पुस्तक के प्रथम संस्करण की 4,74,000 प्रतियां छपीं। यह पुस्तक पहले चीनी भाषा से फ्रांसीसी भाषा में अनूदित हुई और 1976 में प्रकाशित हुई। फिर नार्मन बेथ्यून इंस्टीच्यूट, टोरण्टो (कनाडा) ने इसका फ्रांसीसी से अंग्रेजी में अनुवाद कराया और 1976 में ही इसे प्रकाशित भी कर दिया। प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद मूल पुस्तक के इसी अंग्रेजी संस्करण से किया गया है।

– सम्पादक

मई दिवस पर विविध कार्यक्रमों के आयोजन

श्रमिक जन मुक्त होंगे फिर, समय का ज्ञान कहता है!

बिगुल संवाददाता

लखनऊ, । मई। मई दिवस वह दिन है जब भारत ही नहीं पूरी दुनिया का मेहनतकश अवाम, इंसान द्वारा इंसान के शोषण और दमन के खिलाफ अपनी संग्रामी एकजुटता का प्रदर्शन करता है। भूख, गरीबी और जिल्लत की ज़िन्दगी से मुक्ति की प्रतिज्ञा करता है। भूमण्डलीकरण के इस दौर में, जबकि दुनिया भर के पूंजीवादी लुटेरों ने मेहनतकश अवाम पर मुश्तरका हमला बोल दिया है, जब उदारीकृत नयी आर्थिक नीतियों के जबर्दस्त हमले ने मज़दूर वर्ग को काफी पीछे ठेल दिया है, जब लम्बे संघर्षों से अर्जित श्रम कानूनों पर भी डकैती डाली जा रही है, तब मई दिवस पर जबर्दस्त एकताबद्ध प्रदर्शनों रैलियों ने न केवल मज़दूरों की शक्ति का अहसास कराया, बल्कि नये संघर्षों के शंखनाद के साथ यह विश्वास जताया कि 'पराजय झेलकर ही क्रान्तियां परवान चढ़ती हैं।'

रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)। 'दुनिया के मज़दूरो एक हो!' के गगनभेदी नारे के साथ विभिन्न जगहों पर मनाये गये मई दिवस आयोजनों की कड़ी में ही ऊधमसिंह नगर जिले में भी मज़दूरों ने अपने एकताबद्ध संकल्प को दोहराया। 'मई दिवस आयोजन समिति' के तत्वावधान में रुद्रपुर के विभिन्न ट्रेड यूनियनों और सामाजिक संगठनों द्वारा रैली, आमसभा और मज़दूर विरोधी आर्थिक नीतियों व नये श्रम कानून का पुतला फूंका गया। लाल झण्डे के साथ सरकारी अस्पताल से प्रारम्भ रैली में सैकड़ों की संख्या में मेहनतकश महिलाओं, पुरुषों व बच्चों ने भागीदारी की। इन्द्रा चौक, गल्ला मण्डी, भगतसिंह चौक मुख्य बाजार होते हुए रैली गांधी पार्क पहुंचकर आम सभा में तब्दील हो गयी।

सभा को सम्बोधित करते हुए **'श्रीराम होण्डा श्रमिक संगठन'** के अध्यक्ष **रामचन्द्र शर्मा** ने कहा कि, 1886 की पहली मई को शिकागो के बहादुर मज़दूरों ने 'काम के घंटे आठ करो' का जो नारा बुलन्द किया था, वह आज देश के मज़दूर आन्दोलन के लिए नया अर्थ ग्रहण कर चुका है। आज जबकि लम्बे संघर्षों से मिले सीमित अधिकारों तक को छीना जा रहा है तब मज़दूर वर्ग को पूंजीवादी हुक्मरानों के सामने अपना नया चार्टर पेश करना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक से जारी उदारीकरण की नीतियों ने मज़दूरों की तबाही-बर्बादी और बढ़ाई है और अब पूंजीपतियों की टट्टू भाजपा सरकार श्रम कानूनों पर भी डकैती डाल रही है। उन्होंने कहा कि जाति-धर्म-क्षेत्र के संकीर्ण बंटवारे को छोड़कर मज़दूरों की व्यापक एकता के दम पर ही अपने अधिकारों को बचाया जा सकता है।

आनन्द निशिकावा श्रमिक संगठन के अध्यक्ष **प्रयाग भट्ट** ने कहा कि मज़दूर संघर्षों के बिखराव के कारण ही पूंजीवादी सत्ताधारियों के हौसले बुलंद हैं और चारों तरफ छंटनी-तालाबन्दी एवं दमन का दौर चल रहा है। उन्होंने तराई के पैमाने पर तमाम कारखानों में मालिकों के बढ़ते दबाव पर आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि अब व्यापक एकताबद्ध संघर्षों के द्वारा ही मज़दूरों की जीत संभव है।

बिगुल मज़दूर दस्ता के मुकुल ने कहा कि मई दिवस कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मेहनती जनता के लिए प्रेरणा का दिन है, अपने मुक्तिकामी संघर्ष के लिये नया संकल्प बांधने का दिन है। उन्होंने कहा कि आज वक्ती तौर पर मज़दूर आन्दोलन थोड़ा पीछे गया है और विश्व साम्राज्यवादी ताकतों एवं उनके छुटभैये देशी पूंजीवादी लुटेरों का नापाक गठबन्धन मज़दूर आन्दोलन पर हावी होता दिखलाई दे रहा है। लेकिन वे तब तक ही मजबूत हैं, जब तक हमारी एकता बिखरी हुई है। साम्राज्यवाद महज एक कागजी बाघ है जो मज़दूर एकता की छोटी पहल से ही भयभीत होने लगता है, और जब मेहनतकशों की वर्गीय एकता मजबूत हो जाती है तो उसकी दहाड़ म्याऊं में बदल जाती है। उन्होंने कहा कि बारूद के ढेर जगह-जगह एकत्रित हैं लेकिन इसके विस्फोट के लिये विचारधारा के पलीते की आवश्यकता है। आज एक बार फिर मई दिवस के सच्चे वारिसों की मज़दूर आन्दोलन में क्रान्तिकारी नेतृत्व पैदा करने की जरूरत है, इसके लिये आन्दोलन के भितरघातियों की पहचान भी जरूरी है।

भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ के शाखा सचिव **रामपाल सिंह** ने कहा कि, वर्तमान शासन व्यवस्था मज़दूरों कर्मचारियों के लिये एक धोखा है। उन्होंने कहा कि 1947 में जो अधूरी आजादी मिली थी और तब आम जनता को जो थोड़ी बहुत भी सहूलियतें मिल गयी थी, आज वह भी छिन रही है। 10 फीसदी मुनाफाखोरों के ऐशोआराम के लिये 90 फीसदी मेहनतकशों की तबाही बढ़ रही है। उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर उजाड़े गये मज़दूरों व बाल्को प्रकरण का जिक्र करते हुए बताया कि अब कार्यपालिका के साथ ही न्यायपालिका का भी आम जनविरोधी चरित्र खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने पिछले एक दशक से जारी उदारीकरण की नीतियों की चर्चा करते हुए बताया कि इस दौरान लगभग ढाई लाख छोटे-बड़े कारखाने बन्द हो चुके हैं और लगभग तीन करोड़ मज़दूर सड़कों पर ढकेले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस शोषण से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि मेहनतकश का राज्य स्थापित हो।

प्राथमिक शिक्षक संघ के **अध्यक्ष बिशन सिंह** ने कहा कि वर्तमान शासक वर्ग साम्राज्यवादी लुटेरों के अधीन काम कर रहा है, हमें इसकी पहचान करनी होगी। **राजकीय डिग्री कालेज, रुद्रपुर की उपाध्यक्ष सुश्री अमनदीप कौर** ने 1886 के मज़दूर संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मज़दूरों के खून से ही लाल रंग के झण्डे का जन्म हुआ था। उन्होंने व्यापक एकजुटता की बात करते हुए क्रान्तिकारी कवि पाश की कविता 'हम लड़ेंगे साथी' का पाठ किया।

मज़दूर-किसान संघर्ष समिति के **दिनेश कुमार** ने मज़दूर-मज़दूर के विभेद को मिटाने की बात की और कहा कि कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को खेतों-खलिहानों में काम करने वाले श्रमिकों के साथ मिलकर संघर्ष करना होगा। **सफाई कर्मचारी यूनियन** के **राजवीर** ने कहा कि पूंजीपति जो कानून बना रहा है उससे मज़दूरों का दमन और बढ़ेगा, भुखमरी-बेकारी और बढ़ेगी और जनता में त्राहि-त्राहि मच जायेगी।

नारी सभा की **तारा** ने कहा कि आज नारी दोहरे शोषण का शिकार है। एक तरफ वह सरकार की आम जनविरोधी नीतियों से बढ़ती महंगाई, बेकारी और मज़दूरों की बढ़ती तबाही-बर्बादी का सीधा सामना कर रही है, वहीं दूसरी तरफ, उसे नारी विरोधी मानसिकता को भी भोगना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ महिलाओं को संगठित होना होगा और मज़दूरों-किसानों के साथ मिलकर अपने मुक्तिकामी संघर्षों को तेज करना होगा।

'क्रान्तिकारी लोक अधिकार संगठन' के **मनोज** ने केल्वीनेटर कम्पनी का उदाहरण देते हुए कहा कि किस प्रकार विदेशी कम्पनी ने बलपूर्वक गठजोड़ के बाद वहां आठ हजार मज़दूरों की छंटनी कर दी। आज यही हालात पूरे देश में कायम हो रहे हैं। इस भीषण शोषण से मुक्ति का एक ही रास्ता हो सकता है कि मेहनतकशों का राज कायम हो और यह एक शुभ संकेत है कि पूरी दुनिया का मज़दूर संगठित हो रहा है। **व्यापार कर विभाग** के कर्मचारी नेता **ज़मीर हसन खान** ने इस अवसर पर सरकारी कर्मचारियों की कम मौजूदगी पर आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि आज दरबे में सिमटने की नहीं बाहर निकलकर संघर्ष करने की जरूरत है।

उत्तरांचल राज्य कर्मचारी शिक्षक संघ के **अध्यक्ष पी.सी. शर्मा** ने कहा कि, कर्मचारियों की जो मिली हुई सुविधाएं छिन रही हैं, उसे व्यापक संघर्ष से ही बचाया जा सकता है। **जन एकता मंच** के **देवराज** ने उदारीकरण के वर्तमान दौर में आम जनता की बढ़ती तबाही व बर्बादी की चर्चा करते हुए फासीवाद के बढ़ते खतरे से आगाह किया। **बार एसोसिएशन, रुद्रपुर** के **अध्यक्ष सुभाष छाबड़ा** ने सभी चुनावी पार्टियों को एक ही थैली का बताया जिनका झगड़ा नीतियों का नहीं कुर्सी का है। विलासपुर से आये **यू.पी. कोआपरेटिव** के **सन्तोष पाण्डे** ने कहा कि मज़दूरों की व्यापक एकता के दम पर ही पूंजीवाद को उखाड़ फेंका जा सकता है। **क्रालोस** के **शिवदेव सिंह** ने कहा कि, हालात अब ऐसे बन गये हैं कि श्रमिक वर्ग को एक मंच तथा झण्डे के नीचे आना ही होगा, तभी मेहनतकश की मुक्ति संभव है। सभा का संचालन **बिगुल मज़दूर दस्ता** के **अमर सिंह** ने किया। कार्यक्रम में **बेबी पिंकी** और **बिगुल मज़दूर दस्ता** की टोली ने क्रान्तिकारी गीत प्रस्तुत किये।

इस पूरे आयोजन में सक्रिय भागीदारी करने वालों में **बैंक कर्मचारी मंच (ऊधमसिंह नगर), चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कर्मचारी संगठन, रुद्रपुर** भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरपालिका, विद्युत सहित तमाम विभागों के कर्मचारी व **ईस्टमैन ऐग्रो लि.** सहित तमाम कारखानों के मज़दूरों ने भी शिरकत की।

इस आयोजन में साझा स्पिरिट पैदा करने और इसे व्यापक स्वरूप देने के उद्देश्य से **बिगुल मज़दूर दस्ता** और **श्रीराम होण्डा श्रमिक संगठन** की टोलियों द्वारा सघन प्रचार अभियान चलाया गया। रुद्रपुर में छोटी-छोटी नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गयीं तो खटीमा, सितारगंज, किच्छा, पन्तनगर, मरकोटा, लालकुआं, हल्द्वानी, काशीपुर, गदरपुर, विलासपुर आदि जगहों पर प्रचार अन्य माध्यम से किया गया। रुद्रपुर से दूर वाले इलाकों में यह सुझाव रखा गया कि वहां भी साझा तौर पर ही मई दिवस मनाया जाये। अन्य संगठनों के भी प्रयास से नैनीताल के तराई-भाबर क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भी मई दिवस मनाया गया।

मई दिवस के शहीदों के सपनों को साकार करो!

मर्यादपुर, मऊ। देहाती मज़दूर किसान यूनियन व नारी सभा की ओर से मई दिवस के अवसर पर मर्यादपुर में आयोजित सभा में मज़दूरों की ऐतिहासिक शहादत को याद करते हुए साम्राज्यवादी, पूंजीवादी शोषण-उत्पीड़न को समाप्त करने का संकल्प लिया गया। सभा के पूर्व मऊ जिले के विभिन्न गांवों में साइकिल जुलूस निकाला गया व जगह-जगह सभाएं आयोजित की गईं व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। साइकिल जुलूस सुबह मर्यादपुर बस स्टैण्ड से शुरू होकर ढिलही, ढढवल, गुरमहा, प्यारेपुर, मयादी, मारुखपुर, लघुआई, मीरपुर, डुमरी होते हुए शाम को मर्यादपुर बाजार में पहुंचकर आम सभा में बदल गई।

देहाती मज़दूर किसान यूनियन के संयोजक डा. दूधनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता का मज़दूर विरोधी चरित्र अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। 1990 से आरंभ मज़दूर विरोधी नई आर्थिक नीति को आज भाजपा गठबंधन जिस बदहवासी के साथ लागू करते हुए पूंजीपतियों की सेवा कर रही है। उसने मेहनतकश जनता को पूरी तरह से तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज श्रम कानूनों को बदलकर मज़दूरों के रहे-सहे जनवादी अधिकारों को भी छीना जा रहा है, आयात-निर्यात नीति के जरिए मज़दूरों-किसानों को अपने जगह-जमीन से उजाड़ने के सारे सरंजाम पूरे कर लिये गये हैं। उन्होंने कहा कि मेहनतकश विरोधी इस व्यवस्था के खिलाफ आज मेहनतकश वर्ग को अपनी व्यापक संग्रामी एकजुटता कायम करते हुए संघर्ष को तेज करना होगा और इस व्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील ठोंककर ही सांस लेना होगा।

देहाती मज़दूर किसान यूनियन के कार्यकर्ता हरिहर यादव ने कहा, इतिहास गवाह है कि पूंजीपति हर हमेशा अपने मुनाफे के लिए आम जनता को अमानवीय हदों तक जाकर लूटता-खसोटता है और पूंजीपति की हिमायती संसदीय चुनावी पार्टियां पूंजीपति की समस्याओं को आम जनता की समस्या बनाकर पेश करती है, राष्ट्र के नाम पर पूंजीपतियों के हितों को पूरा करती है। यह पूंजीवादी व्यवस्था कोई अपवाद नहीं है। इसलिये मई दिवस के शहीदों को आज सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके सपने को साकार करने के लिए संघर्ष की धार को तेज किया जाय और सड़कों पर उतरा जाये।

देहाती मज़दूर-किसान यूनियन के इन्द्रदेव ने कहा कि, सरकार की नई नीतियों ने क्षेत्र के छोटे-मोटे उद्योगों को तबाह कर दिया है जिससे कामगारों की जीविकोपार्जन की समस्या उठ खड़ी हुई है। इन्हीं नीतियों के चलते छोटी किसानी से लागत निकाल पाना कठिन हो रहा है। छोटे व्यापारियों का भी अस्तित्व खतरे में है। ऐसे में हमारे पास संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

सभा के बाद देहाती मज़दूर-किसान यूनियन व नारी सभा की संयुक्त सांस्कृतिक टोली ने क्रांतिकारी बिरहा का कार्यक्रम पेश किया। सांस्कृतिक टोली में निर्मला, शिक्षा, लालू, सोना, किशोरी, अशोक व मनोज शामिल थे। जनसभा व सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन 'बिगुल मज़दूर दस्ता' के आदेश कुमार ने किया।

परिकल्पना प्रकाशन की प्रस्तुति

मां

वास्तविक घटनाओं पर आधारित **1905-7 की पहली रूसी क्रान्ति के समय** लिखी गई और समूची दुनिया के पाठकों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय पुस्तक **गोर्की** की यह पुस्तक महज एक मज़दूर परिवार की नियति का चित्रण करने के बजाय समूचे सर्वहारा वर्ग के भविष्य को विलक्षण शक्ति के साथ चित्रित करती है।

मूल्य : 70 रुपये

प्राप्त करें :

जनचेतना

डी-68, निराला नगर, लखनऊ-226 020

फोन : 788932

जनमुक्ति की अमर गाथा : चीनी क्रान्ति की सचित्र कथा (भाग पन्द्रह)

ऐतिहासिक नवीं कांग्रेस और सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति नये चरण में

1. एक अप्रैल 1969 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ऐतिहासिक नवीं कांग्रेस का उद्घाटन हुआ। सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के विगत लगभग तीन वर्षों की अवधि का समाहार करते हुए नवीं कांग्रेस की रिपोर्ट में पहली बार समाजवादी संक्रमण की पूर्ण अवधि के लिए आम दिशा प्रस्तुत की गई।

नवीं कांग्रेस की रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि चीन की सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति कम्युनिस्ट समाज की ओर आरोहण के दौरान विश्व सर्वहारा द्वारा विजित सर्वोच्च चोटी है। इसने सर्वहारा क्रान्ति के विज्ञान को एक नई मंजिल तक विकसित किया है। इसके पीछे सर्वहारा वर्ग के समग्र ऐतिहासिक अनुभवों के निचोड़ का कुल योग है। इस मंजिल तक पहुंचकर माओ ने समाजवादी समाज में वर्ग संघर्ष की प्रकृति, पूंजीवादी पुनर्स्थापना के भौतिक आधारों और संशोधनवाद के सामाजिक आधारों को स्पष्ट रूप में उद्घाटित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराने शत्रु वर्गों के अतिरिक्त छोटे पैमाने के माल-उत्पादन से पैदा होने वाले नये बुर्जुआ तत्वों, पुराने सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों-संस्थाओं, बुर्जुआ अधिकारों, मूल्य के नियम और माल-अर्थव्यवस्था की मौजूदगी और साथ ही, गांव और शहर के बीच, किसान और मजदूर के बीच तथा बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम के बीच असमानता की मौजूदगी और इस स्थिति से लगातार पैदा होने वाली संस्कृति, संस्थाओं एवं विचारों के चलते, समाजवादी समाज में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना का खतरा लगातार लम्बे समय तक मौजूद रहता है। माओ ने स्पष्ट बताया कि पूंजीवादी पुनर्स्थापना को रोकने के लिए सर्वहारा अधिनायकत्व के अन्तर्गत वर्ग-संघर्ष को लगातार जारी रखना होगा, बुर्जुआ अधिकारों, उपयोग में असमानता और भौतिक प्रोत्साहन को लगातार सीमित करते जाना होगा तथा शिक्षा-संस्कृति और सामाजिक-राजनीतिक ऊपरी ढांचे में सतत क्रान्ति जारी रखनी होगी। इस प्रक्रिया में, पार्टी और राज्य के ढांचे में जमे पुराने व नये बुर्जुआ तत्व लगातार अड़चने पैदा करेंगे और उनके विरुद्ध व्यापक जन समुदाय को जागृत करके राजनीतिक संघर्ष चलाना अनिवार्य होगा।

माओ त्से-तुङ ने तत्कालीन सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति को अपने ढंग की पहली क्रान्ति बताते हुए भविष्य में ऐसी कई क्रान्तियों की आवश्यकता अपरिहार्य बताई और आगाह किया कि "क्रान्ति में कौन विजयी होगा, यह मसला एक लम्बी ऐतिहासिक अवधि के बाद ही तय हो सकेगा।"

1. प्रगति के चमत्कारी कीर्तिमान स्थापित करने वाले, थाएहू ज़ील पर स्थित तुङथिङ जन कम्यून के एक उत्पादक–ब्रिगेड के सदस्य पहाड़ियों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाते हुए

2. उत्पादक श्रम में भाग लेते तुङथिङ जन कम्यून के नेतागण

3. नई छलांग की योजना बनाती तुङथिङ जन कम्यून की पार्टी–कमेटी

4. *क्रान्ति को कमान में रखो, उत्पादन को आगे बढ़ाओ*'––सांस्कृतिक क्रान्ति के इस प्रसिद्ध नारे ने उत्पादन–वृद्धि और तकनीकी प्रगति के नये कीर्तिमान कायम किये। पूर्वी होपेई प्रान्त के पहाड़ी गांव शाशिहयू का एक खलिहान, जहां पहले सिर्फ बंजर पथरीली जमीन थी।

5. पूर्वी होपेई प्रान्त के शाशिहयू गांव में किसानों द्वारा क्रान्तिकारी आलोचना के जनान्दोलन की शुरुआत।

6. माओ के विचारों का अध्ययन और संशोधनवाद की आलोचना करते शंघाई के मजदूरों के अध्ययन–दल

7. (ऊपर) पार्टी सदस्यों से घिरे हुए माओ, पीकिङ, 1 मई 1967

8. (नीचे) शाशिहयू गांव में त्सुन्हुआ काउण्टी की नाट्यमंडली की एक प्रस्तुति

9. (दाएं) सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान बुर्जुआ वर्ग और उसकी विचारधारा एवं संस्कृति के विरुद्ध संघर्ष में चियाङ चिङ के नेतृत्व में पीकिङ ऑपेरा ने अहम भूमिका निभाई। उस दौर की प्रसिद्ध नृत्य–नाटिका 'स्त्रियों का लाल दस्ता' का एक दृश्य

2. नवीं कांग्रेस में जो नई केन्द्रीय कमेटी चुनी गई उसमें सिर्फ 40 प्रतिशत सदस्य पहले के थे। बाकी बड़ी संख्या में किसानों, मजदूरों और सैनिकों के नये प्रतिनिधि थे।

सांस्कृतिक क्रान्ति के प्रथम ज्वार के पहले चरण का समाहार हो चुका था, पर संघर्ष अभी भी जारी था–पहले से भी कहीं अधिक गहरे, व्यापक और प्रचण्ड रूप में। नवीं कांग्रेस के समय से ही लिन प्याओ ने यह कहते हुए माओ की शिक्षा का निषेध करना शुरू कर दिया था कि सांस्कृतिक क्रान्ति अब सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुकी है, समाजवाद की विजय सुनिश्चित हो चुकी है और अब चीन में उत्पादन बढ़ाने पर ही जोर दिया जाना चाहिए। लिन प्याओ एक कैरियरवादी था, जो माओ का झण्डा जोर-शोर से लहराते हुए, सतत क्रान्ति की प्रक्रिया को रोककर अपने नये बुर्जुआ गुट की सत्ता को पार्टी और राज्य पर प्रभावी बनाना चाहता था। जनता की जगह वह सेना की भूमिका को निर्णायक बनाना चाहता था और लाल सेना को एक बुर्जुआ सेना में तब्दील कर देना चाहता था। वह उग्र वामपंथी लफ्फाजी की आड़ में उत्पादक शक्तियों के विकास के दक्षिणपंथी कार्यक्रम को लागू करना चाहता था।

समाजवाद की शक्तियों के सामने एक ही नहीं बल्कि कई एक बुर्जुआ धड़े सक्रिय थे और उन सबका आधार पिछड़े हुए चीनी समाज के भीतर ही मौजूद था। माओ के साथ खड़े क्रान्तिकारियों को सत्ताच्युत ल्यू शाओ-ची के पार्टी में अब भी मौजूद साथियों के साथ ही लिन प्याओ के साजिशी गिरोह से और चाऊ एन-लाई आदि के मध्यमार्गी गुट से भी जूझना पड़ रहा था। जब किसी एक गुट से अन्तरविरोध प्रधान होता था तो तत्क्षण दूसरा गुट उसका लाभ उठाकर अपना आधार-विस्तार करने लगता था। वर्ग-संघर्ष लगातार विकट रूपों में जारी रहा और माओ अपनी आखिरी सांस के साथ पूंजीवादी पथगामियों से जूझते रहे।

नवीं कांग्रेस के बाद पार्टी में अति वामपंथी लफ्फाजी करने वाले नये पूंजीवादी पथगामियों तथा फरमानशाही एवं नौकरशाही के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा गया। इसके लिए क्रान्तिकारी कमेटियों में कार्यक्रमावली पद्धति की शुरुआत की गयी जिसके तहत यह प्रावधान था कि क्रान्तिकारी कमेटी के एक तिहाई सदस्य नेतृत्व की हैसियत से सक्रिय रहेंगे, एक तिहाई रुटीनी कामों को अंजाम देंगे और शेष एक तिहाई अध्ययन करेंगे या फिर 7 मई कैडर स्कूल में आवासी के तौर पर रहेंगे। साथ ही बुनियादी स्तरों पर पार्टी का पुनर्गठन किया गया तथा क्रान्तिकारी कमेटियों एवं सेना पर पार्टी का सुदृढ़ नेतृत्व स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू हुए।

10. सांस्कृतिक क्रान्ति के घटनाक्रम की खबरों के प्रति पूरे देश की जनता में व्यापक उत्सुकता थी

3. सितम्बर, 1970 में हुए नवीं केन्द्रीय कमेटी के दूसरे पूर्ण अधिवेशन में लिन प्याओ गुट के विरुद्ध संघर्ष कुछ और तीखा हो गया, जब चेन पो-ता का भण्डाफोड़ करते हुए उसे पार्टी से निकाल दिया गया। अधिवेशन में ल्यू शाओ-ची के हटाये जाने से रिक्त चीन लोक गणराज्य के अध्यक्ष पद पर लिन प्याओ को बहाल करने की "वाम" गुट की साजिश का पता चला, लेकिन लिन प्याओ और उसके समर्थक कुछ शीर्षस्थ सैन्य अधिकारी अभी भी खुले हमले के निशाने पर नहीं आये थे।

फिर सेना और प्रशासन में जड़ जमाए लिन प्याओ समर्थकों के विरुद्ध व्यापक अभियान शुरू हुआ। लिन प्याओ द्वारा सांस्कृतिक क्रान्ति के पहले दौर में निलम्बित कर दी गई जन-मिलिशिया का प्रशिक्षण फिर से शुरू हुआ। अप्रैल, 1971 में एक विशेष मीटिंग बुलाई गई जिसमें पार्टी और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में लिन प्याओ से आत्मालोचना की मांग की गयी।

अगस्त 1971 तक नीचे से लेकर ऊपर प्रान्तीय पार्टी कमेटियों तक के पुनर्गठन का काम पूरा हो चुका था। फिर इसी तरह की प्रक्रिया नागरिक एवं सैनिक संस्थाओं में तथा नये और पुराने दोनों तरह की जन-संस्थाओं व संगठनों में भी लागू की गई।

केन्द्रीय कमेटी के तीसरे पूर्ण अधिवेशन में गणराज्य के अध्यक्ष का प्रश्न फिर उठा। विचार-विमर्श के बाद, इस पद को खत्म कर देने और सामूहिक नेतृत्व की स्थापना का फैसला लिया गया। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी होने के आसार न देखकर लिन प्याओ ने माओ की हत्या और फौजी विद्रोह के द्वारा सत्ता कब्जा करने की योजना बनाई लेकिन इसका भण्डाफोड़ हो गया। सोवियत संघ की ओर भागने की कोशिश करते हुए लिन प्याओ का जहाज मंगोलिया में गिर गया और उसकी मौत हो गयी।

(पेज 8-9 पर जारी)

जनमुक्ति की अमर गाथा: चीनी क्रान्ति की सचित्र कथा (भाग-पन्द्रह)

ऐतिहासिक नवीं कांग्रेस और सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति नये चरण में

11. (ऊपर) 'सफदे बालों वाली लड़की' नृत्य दल की सदस्यांएं क्वाङसी के वेङनिऊ गांव के पहाड़ी रास्ते पर, जहां रहकर उन्हें जनता के जीवन का अध्ययन करना था और उनके बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने थे। सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान संस्कृतिकर्मी शहरी सांस्कृतिक केन्द्रों से दूर गांवों-कारखानों में जाकर जनजीवन का अध्ययन करते थे ताकि क्रान्तिकारी संस्कृति व्यापक आम जनता तक जा सके और सर्वहारा क्रान्ति की सेवा कर सके।

4. लिन प्याओ के पतन से पार्टी में चाऊ एन-लाई और उनकी मध्यमार्गी लाइन की स्थिति काफी मजबूत हो गयी। चाऊ एन-लाई के साथ माओ का पुराना सहयोगी होने की साख भी जुड़ी थी। पर उनकी मध्यमार्गी लाइन का लाभ अंततः दक्षिणपंथी ताकतों को ही मिला। राजनीतिक संघर्ष में शक्ति-संतुलन की यह विवशता थी कि लिन प्याओ गुट के लोगों को हटाए जाने से रिक्त

(पेज 9 पर जारी)

14. (नीचे) सांस्कृतिक क्रान्ति की प्रकृति अंतरराष्ट्रीयतावादी थी। 1968 में अमेरिकी अश्वेत जनता के संघर्ष के समर्थन में चीनी जनता का विराट प्रदर्शन

13. (बाएं) पूंजीवादी पथगामियों की आलोचना के पोस्टर लगाते छात्र-युवा

12. (ऊपर) गांवों में सड़क बनाने में जनमुक्ति सेना का हाथ बंटाते छात्र

15. (दाएं) 'सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान कारखाने में वर्ग संघर्ष'- शंघाई न. 3 इंक फैक्ट्री की क्रान्तिकारी समिति के प्रचार ग्रुप द्वारा तैयार किया गया पोस्टर

जनमुक्ति की अमर गाथा: चीनी क्रान्ति की सचित्र कथा (भाग-पन्द्रह)

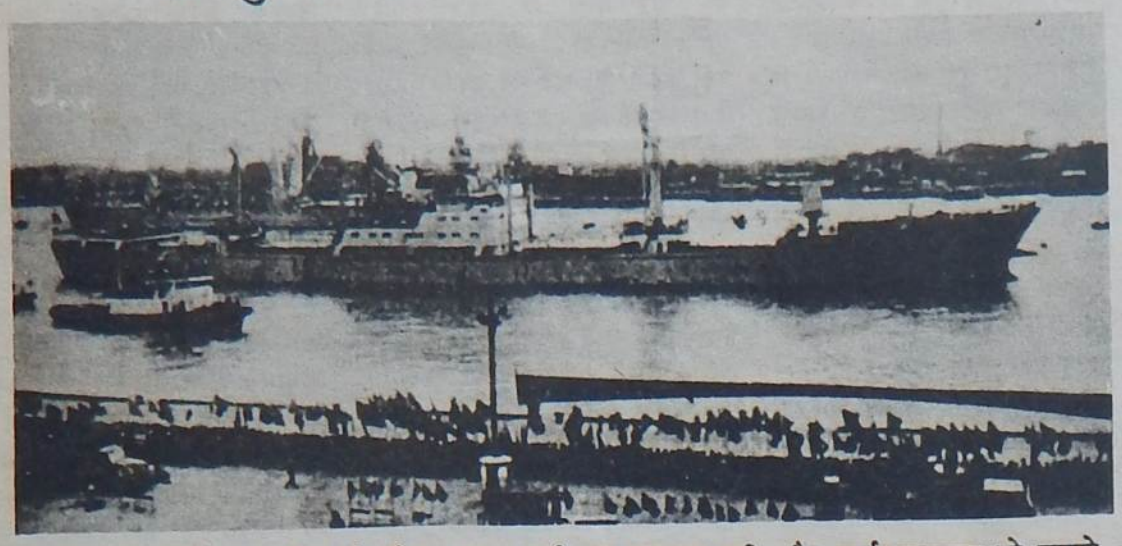

17. (ऊपर) सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान मुक्त हुई जन-पहलकदमी और सर्जनात्मकता के सहारे विज्ञान और तकनोलाजी की प्रगति का एक नमूना : पूरी तरह स्वदेशी तकनोलाजी और कल-पुर्जों से, शंघाई गोदी के मजदूरों द्वारा निर्मित 10 हजार टन क्षमता वाला मालवाहक जहाज 'फेङगुआङ'

पृष्ठ 8 से आगे

हुए स्थानों को भरने के लिए पुन: ल्यू शाओ-ची – देङ सियाओ-पिङ गिरोह के बहुतेरे दक्षिणपंथी भी ''अतिरेक गलतियों को सही किये जाने'' की आड़ में पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर बहाल हो गये। दक्षिणपंथी दिन में सांस्कृतिक क्रांति का ''समर्थन'' करते थे और रात में अपनी पोजीशन मजबूत बनाने का काम करते थे। जो वापमंथी क्रान्तिकारी धड़ा माओ के सर्वहारा हेडक्वार्टर की हिफाजत में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा था, उसकी अगुवाई मुख्यत: चाङ चुन-चियाओ, चियाङ चिङ, वाङ हुङ-वेन और याओ वेन-युआन कर रहे थे। चाङ-चियाओ, 'महान अग्रवर्ती छलांग' से लेकर सांस्कृतिक क्रान्ति के दौर में एक अग्रणी सिद्धांतकार के रूप में सामने आये थे, जबकि माओ की पत्नी चियाङ-चिङ मुख्यत: संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक क्रांति की धारा को नेतृत्व दे रही थीं। वाङ और याओ सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान नीचे से उभरे युवा नेताओं के रूप में सामने आये थे।

1973 में देङ सियाओ-पिङ फिर से अपने पद पर बहाल हो गया। दक्षिणपंथी अवसरवादी गुट लिन प्याओ के पतन से पैदा हुई स्थिति का भरपूर लाभ उठाते हुए आधार फिर मजबूत बना रहा था। लेकिन इसके बावजूद अगस्त 1973 में हुई पार्टी की दसवीं कांग्रेस में सांस्कृतिक क्रांति की लाइन विजयी रही। चियाङ चिङ, चाङ चुन चियाओ, वाङ हुङ-वेन और याओ वेन-युआन पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के राजनीतिक ब्यूरो में चुने गये, लेकिन स्टैण्डिंग कमेटी में सिर्फ चाङ चुन-चियाओ ही ऐसे थे जो पूरी तरह माओ के शिविर में थे। दसवीं कांग्रेस के बाद माओ ने दक्षिणपंथी धारा के विरुद्ध अपने जीवन के अंतिम महान संघर्ष का बिगुल फूंक दिया।

5. दसवीं कांग्रेस ने सांस्कृतिक क्रान्ति के नारे-'क्रान्ति पर पकड़ बनाये रखो, उत्पादन को आगे बढ़ाओ'- को पूरी तरह स्वीकार किया था। इस समय तक आते-आते सांस्कृतिक क्रान्ति से चीनी समाज में अराजकता फैल जाने की पश्चिमी दुनिया की सारी भविष्यवाणियां निर्मूल साबित हो चुकी थीं। उथल-पुथल के प्रारम्भिक वर्षों के बाद चीन के ग्रामीण और औद्योगिक जन कम्यूनों में उत्पादन वृद्धि के नये कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे। सत्तर के दशक में विश्व अर्थव्यवस्था संकटों के बोझ से चरमरा रही थी, लेकिन चीनी अर्थतंत्र प्रगति की नई छलांगे भर रहा था। कृषि के क्षेत्र में ताचाई और उद्योग के क्षेत्र में ताचिङ के माडलों की पूरी दुनिया में

18. (दाएं) सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान माओ की कृतियां और मार्क्सवादी क्लासिकी साहित्य बड़े पैमाने पर पूरे देश में जन-जन तक पहुंचाया गया। क्वेइचो प्रान्त के एक सुदूर पहाड़ी गांव में साहित्य लेकर आये कार्यकर्ता का स्वागत करते मियाओ जाति के लोग

16. (बाएं) गरीब किसान से सीखते हुए शहर के छात्र

20. (बाएं) पीकिङ क्रान्तिकारी कमेटी के सामने भाषण देती हुई चियाङ चिङ, 1968

19. (दाएं) रेड गार्डों के साथ एक बैठक में चियाङ चिङ 1967

चर्चा हो रही थी। बिना किसी विदेशी मदद के, चीन में जहाज निर्माण से लेकर रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति की नई-नई मिसालें कायम हो रही थीं। यही नहीं, सैद्धान्तिक भौतिकी और जैविकी के क्षेत्र में भी नई-नई खोजें हो रही थीं।

सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान उत्पादन से लेकर संस्कृति और समाज तक के क्षेत्र में ''नई समाजवादी चीजें'' अस्तित्व में आई। ''नंगे पैर'' डाक्टरों के प्रयोग ने स्वास्थ्य-सुविधाओं को जन-जन तक के लिए सुलभ बना दिया। स्त्रियां चूल्हे-चौखट की गुलामी से मुक्त होकर बड़े पैमाने पर उत्पादक सामाजिक कार्रवाइयों और राजनीति में हिस्सा लेने लगीं। उत्पादन और विनिमय के क्षेत्र में पूंजीवादी असमानता की बुनियाद पर पहली बार इतनी निर्णायक चोट की गयी थी। लेकिन पूंजीवादी पथगामी अभी भी अपने रास्ते पर थे और नवोदित समाजवाद को परास्त करने के लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक किये हुए थे।

अगले अंक में जारी

(पृष्ठ । से आगे)

इंडियन लेबर का संदेश क्या है?

इंडियन लेबर कांफ्रेंस की तर्ज पर प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बुलाये जायेंगे।

सम्मेलन के पहले दिन बी.एम.एस. महासचिव हंसमुख भाई दवे ने चिरपरिचित फासिस्ट लफ्फाजी के अन्दाज में मज़दूरों के हितों की फर्जी हिमायत करते हुए जोरदार भाषण दिया जो अगले दिन अखबारों में प्रमुखता से छपा। यह भाषण ठीक उसी तर्ज पर था जैसा 16 अप्रैल को दिल्ली में हुई बी.एम.एस. की रैली में दत्तोपंत ठेंगड़ी ने दिया था। हंसमुख भाई दवे ने वाजपेयी सरकार की नीतियों को "मज़दूर, उद्योग और राष्ट्रहित के विरुद्ध" बताया। दरअसल, बी.एम.एस. के सरकार विरोधी तेवर आर.एस.एस. की एक सोची-समझी रणनीति के अंग हैं। नयी आर्थिक नीतियों से देश में जो तबाही मची है, जनता के भीतर जो गुस्सा पनप रहा है, उसे तोड़ते हुए आर.एस.एस. ने यह तेवर अख्तियार किया है। इस तेवर से वह मज़दूर वर्ग के भीतर यह भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि बी. एम.एस. मज़दूर आन्दोलन के भीतर पूंजीपति वर्ग का एजेंट नहीं बल्कि मज़दूरों का हितैषी है। मज़दूरों को बी.एम.एस. के इस झांसे में आने की जरूरत नहीं है। यह वही बी.एम.एस. है जिसकी हड़ताल तोड़क भूमिका और धर्म के आधार पर मज़दूर वर्ग को बांटने की भूमिका जगजाहिर है।

लेकिन अपने परिवार के ट्रेड यूनियन नेता के आग उगलने वाले भाषण पर सम्मेलन में मौजूद प्रधानमंत्री वाजपेयी ने ताली भी नहीं बजायी। उन्होंने ताली सिर्फ तब बजायी जब पूंजीपतियों के प्रतिनिधि ने आर्थिक नीतियों और श्रम कानूनों में बदलाव की हिमायत करते हुए भाषण दिया। अपनी बारी में प्रधानमंत्री महोदय ने लिखित भाषण को दरकिनार कर खुद निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों के समर्थन में चिरपरिचित भावुक-मसखरे के अन्दाज में जोरदार भाषण पिलाया। उन्होंने कहा कि देश को अगर प्रगतिपथ पर ले जाना है तो इन नीतियों पर चलना ही होगा। श्रम कानूनों में संशोधन की भी उन्होंने जोरदार हिमायत की। यह कहा कि इससे शुरुआत में मज़दूरों को थोड़ी मुसीबत उठानी पड़ सकती है लेकिन आगे चलकर सब ठीक हो जायेगा। उन्होंने झूठे सरकारी आंकड़ों के जरिये यहां तक साबित कर डाला कि पिछले दस सालों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और गरीबी घटी है।

सम्मेलन में दिया गया प्रधानमंत्री का यह भाषण ही सबसे अहम सन्देश है जिसे मज़दूर वर्ग को गम्भीरता से लेना चाहिए। यानी सरकार हर हालत में हर कीमत पर निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों पर बेरोकटोक आगे बढ़ती रहेगी। हर कीमत पर श्रम कानूनों में बदलाव कर मज़दूरों को पूंजीपतियों का गुलाम बना दिया जायेगा जिससे वे खून की आखिरी बूंद तक निचोड़कर अपना मुनाफा पीटते रहें।

प्रधानमंत्री महोदय यह हेकड़ी इसलिए भी दिखा रहे हैं कि उन्हें केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की औकात पता है। वे जानते हैं कि दत्तोपन्त ठेंगड़ी और हंसमुख भाई दवे चाहे जितना चीखे-चिल्लाएं वे उनके ही परिवार के सदस्य हैं, जिनकी अपनी मजबूरियां हैं। ये मजबूरियां सिर्फ रैलियों और मीटिंगों में भाषण देने तक सीमित रहेंगी। कोई जनान्दोलन का तूफान खड़ा करना इनकी मंशा नहीं है।

सीटू और एटक की औकात भी प्रधानमंत्री महोदय अच्छी तरह जानते हैं। आर्थिक सम्प्रभुता पर खतरे के लम्बे-चौड़े भाषणों, कुछेक रैलियों या आधे-अधूरे मन से हड़ताल के नाम पर की गयी कवायदों और गीदड़-भभकियों से आगे ये भी कभी नहीं बढ़ेंगे, इस बात का पक्का भरोसा है प्रधानमंत्री महोदय को। इनकी ताकत और मजबूरियों को भी वे बखूबी समझते हैं। हिन्द मज़दूर सभा के आका जार्ज फर्नांडीज तो उनके मुसीबत के संगी हैं और 'इंटक' से कोई खतरा पैदा होने का सवाल नहीं। लिहाजा वे पूंजीपतियों के नुमाइन्दों के भाषणों पर तालियां पीटते हुए मज़दूरों पर मुस्कुराते हुए चाबुक फटकार सकते हैं।

इस सम्मेलन में भी इन ट्रेड यूनियनों ने अपनी औकात दिखा दी कि विरोध का स्टैण्डर्ड क्या है। इनका कोई प्रतिनिधि इस बात पर नहीं अड़ा कि लम्बे संघर्षों के दौरान मज़दूरों को हासिल अधिकारों में रंचमात्र भी कटौती वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रम कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया क्या हो, तरीका क्या हो, इसी पर वे बहस करते रहे। निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों का क्या असर पड़ रहा है इस पर तू-तू मैं-मैं करते रहे। लेकिन सम्मेलन के अन्त में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव पर सबने दस्तखत किये जिसमें कहा गया है कि निजीकरण-उदारीकरण की नीतियां जारी रहेंगी। सिर्फ प्रस्ताव में यह जोड़ पाये कि निजीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। बाल्को और माडर्न फूड जैसी धांधलीबाजी नहीं होगी और विश्व व्यापार में राष्ट्र के हितों के मद्देनजर सरकार जमकर सौदेबाजी करेगी।

बहरहाल, सम्मेलन से बाहर आने के बाद सभी ट्रेडयूनियनों ने साझा रूप से सरकार को मज़दूर विरोधी नीतियों को लागू करने के लिए एक बार फिर चेतावनी दे डाली है और देशव्यापी आन्दोलन करने की धमकी भी। हो सकता है आने वाले कुछ समय में एकाध बड़ी रैलियां – भारत बन्द का आह्वान भी हो जाये, लेकिन इतना तय है कि ये ट्रेडयूनियनें कोई फैसलाकुन जंग का एलान नहीं करने जा रहीं।

फैसलाकुन जंग के लिए तो मज़दूर वर्ग को ट्रेड यूनियन नौकरशाहों के चंगुल से आज़ाद होकर नयी तैयारियों में जुटना होगा। अपना नया नेतृत्व तैयार करना होगा।

(पृष्ठ । से आगे)

जापानी डकैतों के लूट का एक...

दूसरे, वे सदैव कारखानों में अनिश्चितता का माहौल बनाये रखते हैं। कभी किसी मशीन को उखाड़कर दूसरे जगह स्थानान्तरित कर देंगे। कभी कोई कम्पोनेंट ठेके पर दे देंगे तो कभी पुराने की जगह नया प्लांट शिफ्ट कर देंगे। उनके कारखानों में हमेशा संशय-दुविधा का माहौल व्याप्त रहता है।

तीसरे, वे एक जगह पर पूरे कारखाने को एक साथ नहीं चलाते हैं। वे पूरे असेंबली लाइन को बिखरा देते हैं। इंसेलरीज में ज्यादा से ज्यादा काम करवाने, पीस रेट पर विशेषतया स्त्रियों से सस्ती दरों पर काम करवाने पर वे अमल करते हैं। इससे एक तो मज़दूरों की ज्यादा आबादी एक साथ संगठित नहीं हो सकती, दूसरे इनकी मनमानी लूट जारी रहती है।

ये मज़दूरों की यूनियनबद्धता को रोकने की हरचन्द कोशिश करते हैं, अथवा यूनियनों को प्रबन्धतन्त्र के हाथों में बांधने का प्रयास करते हैं। वे श्रम कानूनों पर अपनी पूरी पकड़ रखते हैं और उसे अपने हित के अनुरूप ढालने-बनाने के लिये कृतसंकल्प रहते हैं। यूं तो भारत में 'हायर एण्ड फायर' की तर्ज पर मौजूदा श्रम कानूनों को "लचीला" करने – छंटनी, तालाबन्दी, ले आफ की खुली छूट वाले श्रम कानून पारित करवाने के लिए विश्व के सभी साम्राज्यवादी लुटेरों से लेकर उनके छुटभैये देशी पूंजीपतियों तक का जोर रहा है। लेकिन जापानी डाकुओं की हड़बड़ी ज्यादा रही है और भारतीय शासकों पर अपेक्षतया उनका जयादा दबाव रहा है। यही कारण है कि श्रम आयोग की रिपोर्ट आने से पूर्व ही (जाहिरा तौर पर उसका स्वरूप भी 'हायर एण्ड फायर' के तर्ज पर ही होगा) वित्तमंत्री ने बजट प्रावधानों के साथ ही श्रम कानूनों में बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा पारित करवा लिया। इस कानून के तहत 1000 से कम स्थायी श्रमिकों वाले कारखानों में (पहले यह 100 श्रमिकों से कम वाले कारखानों में लागू था) औद्योगिक विवाद अधिनियम का अध्याय 5बी लागू नहीं होगा।। यानी ऐसे कारखानों में प्रबन्धतंत्र जब चाहे छंटनी कर सकता है, तालाबन्दी या ले आफ कर सकता है, कहीं से भी कारखाना शिफ्ट कर सकता है। इसके साथ ही ठेका अधिनियम में भी संशोधन करके नियमितीकरण के कानूनी झंझटों से भी मालिकों ने मुक्ति पा ली। उन्हें ठेके पर पूरे कारखाने तक को चलाने की खुली छूट मिल गयी। जल्द ही यह लागू भी हो जायेगा।

चूंकि अधिकतम कारखाने 1000 स्थायी श्रमिकों से कम संख्या वाले हैं, सो मज़दूरों की भारी आबादी तो इसी से प्रभावित हो जायेगी। असेम्बली लाइन बिखराने की पद्धति (जापानी जिसके महारथी हैं) से वैसे भी स्थायी श्रमिकों की संख्या 1000 तक नहीं पहुंच पायेगी।

संकटग्रस्त जापानियों का कहर मज़दूरों पर

स्थिति की भयंकरता का अहसास करने के लिये एक और बात पर भी गौर करना जरूरी है।

दुनिया का दूसरा सबसे सम्पन्न देश जापान पिछले दिनों भयंकर आर्थिक गिरावट (मंदी) के दौर से गुजर रहा था, जिसका इलाज वे तेज आर्थिक सुधारों में देख रहे हैं। इन आर्थिक सुधारों का लक्ष्य श्रमिकों की संख्या घटाकर खर्च में कटौती करना माना जा रहा है। इन जापानी डाकुओं का मानना है कि ऐसी कटौती से उद्योगों की प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ेगी और जापान दुनिया के बाजार में पहले की तरह वरीयता हासिल कर लेगा। जापानियों के इसी वर्तमान संकट का एक पहलू वहां के प्रधानमंत्री पद के लिये जुनिचिरो कोइजुमी का, जो आर्थिक सुधारों का कट्टर समर्थक है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा चुना जाना भी है।

जापानी कम्पनियों में भारतीय श्रमिकों की बढ़ती बेहाली

जापानी डकैतों की उपरोक्त पद्धति और उनके वर्तमान संकट से उबारने वाले आर्थिक सुधारों की रणनीति के आइने में भारत में दोहन कर रही उनकी तमाम कम्पनियों में काम कर रहे श्रमिकों की स्थिति को देखा-समझा जा सकता है। चाहें होण्डा, सुजुकी, कावासाकी हो अथवा निशिकावा या सोनी, कमोबेश हर जगह एक ही तरह का डण्डा चल रहा है। उदाहरण के तौर पर आइए देखें जनरेटर बनाने वाले 'होण्डा पावर प्रोडक्ट्स' को।

रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) में इस कारखाने की स्थापना डेढ़ दशक पूर्व उस वक्त हुई थी, जब भारतीय बाजार वैश्विक लुटेरों के लिये थोड़ा सा खुला था। और तराई सहित जगह-जगह रेवड़ी की तरह सब्सिडियां बांटी जा रही थीं। उस वक्त देशी पूंजीपति श्रीराम ग्रुप के साथ मिलकर 'श्रीराम होण्डा पावर प्रोडक्ट्स' की स्थापना हुई थी। बाद में नीतियां और उदार हुईं और श्रीराम ग्रुप मुनाफा बटोरकर अपनी पूंजी सहित इससे बाहर हो गया, अब यह होण्डा की अकेली बपौती बन गयी (छोटी मछली गायब हो गयी बड़ी मछली रह गयी)। धीरे-धीरे यहां के मज़दूरों के अथक परिश्रम से शुरू में पांच करोड़ के घाटे वाला यह कारखाना 25-30 करोड़ के वार्षिक फायदे वाला कारखाना बन गया।

यूं तो शोषण और दमन तो इस कारखाने में शुरू से ही रहा है, लेकिन यहां के श्रमिकों ने स्थायी- कैजुअल-ठेका के विभाजक रेखा को तोड़कर अपने जुझारू एकताबद्ध संघर्षों के दम पर न केवल अपने यूनियन का गठन कर लिया था, बल्कि कई सहूलियतें भी हासिल कर लीं। साथ ही, क्षेत्र के मज़दूर आन्दोलनों में भी शिरकत करके वे अपनी वर्गीय पक्षधरता प्रदर्शित करते रहे हैं। अब जबसे कारखाना होण्डा के आधिपत्य में आया है, दबाव का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है।

कम्पनी ने कुछ कम्पोनेंट (जैसे वेल्डिंग, पेण्टिंग आदि के कुछ हिस्से) अपने इंसलरीज में (ठेके पर) पहले ही दे दिये थे। अभी पिछले दिनों इसने वेल्डिंग शॉप से मफलर लाइन, प्रेस शॉप से डाई, टूलरूम से जिग फिक्शर, पेण्ट शॉप से कुछ और कम्पोनण्ट ठेके पर दे दिये हैं। कारखाने में (जापानी पद्धति में) अनिश्चितता का माहौल कायम है। एल्युमिनियम शॉप और स्टोर आदि के स्थानान्तरण और किश्तों में पूरे कारखाने तक के स्थानान्तरण की अफवाहें (?) व्याप्त हैं। कभी कुछ नये प्लाण्ट लगने की भी हवा फैलती है। कुल मिलाकर उत्पादकता बढ़ाने (रोबोट की तरह काम करवाने) का दबाव बन रहा है। अपने आर्थिक मंदी को यहां भी थोपने का प्रयास चल रहा है – यानी श्रमिकों की संख्या घटाने अथवा तरह-तरह से खर्चे को कम करने की चालें चली जा रही हैं। खर्चे की कटौती का मामला अमानवीयता के उस हद तक पहुंच गया है जहां पानी तक में राशनिंग हो रही है।

कारखाने के बाहर पानी की एक टोटी थी जिसका इस्तेमाल प्रायः ट्रक-बस आदि के ड्राइवर वगैरह करते रहे हैं। अब इसे बन्द कर दिया गया है। यहां के प्रबन्धकों का कहना है कि चूंकि पानी के शुद्धीकरण में काफी खर्चा बैठता है लिहाजा वे इसे खर्चे में कटोती के लिये बन्द कर रहे हैं। यही नहीं श्रमिकों पर दबाव बनाने के लिये तरह-तरह की तिकड़में भी रची जा रही हैं। अभी कुछ श्रमिकों को नोटिस जारी करके निश्चित समयावधि में आयु प्रमाण पत्र मांगा गया (जबकि सबके प्रमाण पत्र कम्पनी की फाइलों में मौजूद हैं, कुछ मज़दूरों ने निकलवाकर दिखलाया भी) जो कइयों के लिये सिरदर्द बन गया था। यूनियन को तोड़ने-कमजोर करने की भी हरचन्द कोशिश जारी है।

यह तो महज एक बानगी है। ऐसी ही त्रासदपूर्ण स्थिति देश के सभी जापानी कारखानों की और इसी तर्ज पर देश के सभी कारखाना मज़दूरों की चाहें मारुति के मज़दूर हों चाहें ठेल्को-बाल्को-सलोश के – बनी हुई है।

तो फिर रास्ता क्या है?

ऐसे कठिन हालात में सर्वोपरि आवश्यकता है मेहनतकशों की व्यापक एकता कायम करना और अपने मुक्तिकामी जुझारू संघर्ष की रणनीति बनाना। इसकी शुरुआत जातिवाद-क्षेत्रवाद- विभागवाद के संकीर्ण बंटवारे की चौहद्दी को तोड़कर कारखाना स्तर पर मज़दूर एकता कायम करते हुए संगठित-असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की इलाकाई एकता कायम करने से होनी चाहिए। रिक्शा वालों-ठेलावालों से लेकर राइस मिल-तेल मिल, स्थायी-अस्थायी, निजी-सरकारी सभी मज़दूरों और खेतों में खटने वाले खेतिहर मज़दूरों तक में व्यापक एकता कायम होनी चाहिए।

ऐसे भी प्रयास होने चाहिए कि एक ग्रुप के कारखाना मज़दूरों की और एक ट्रेड के मज़दूरों की एक ही यूनियन बने। मसलन होण्डा कं. के इस देश में जितने भी कारखाने हों उनके मज़दूरों की एक ही यूनियन हो, आटोमोबाइल क्षेत्र के सभी कारखाना मज़दूरों की एक यूनियन हो, एक ही उत्पाद से प्रत्यक्ष-परोक्ष जुड़े मज़दूर – जैसे आनन्द निशिकावा कं. अथवा ए.एस.पी., मारुति, सुजुकी के कारों के लिये अथवा टाटा कारों के लिये रबर जेन बनाती है तो यहां के मज़दूर परोक्ष रूप से मारुति अथवा टाटा के मज़दूरों से जुड़ते हैं। वे एक यूनियन के बैनर तले भी एकत्रित हो सकते हैं। यानी हर तरफ से मज़दूर आबादी को लुटेरे मालिकों को घेरने का प्रयास तेज करना होगा।

यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि विश्व पूंजीवादी तंत्र अपने मौत के सन्निकट खड़ा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आर्थिक महामंदी के जिस दलदल में वह फंसा है, उससे निकलने की वह जितनी भी कोशिश कर रहा है, उतने ही गहरे धंसता जा रहा है। आर्थिक सुधारों का जो नायाब तरीका वे इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बेरोजगारी और बढ़ रही है जिससे लोगों की क्रय शक्ति कम होती जा रही है फिर बाज़ार और सिकुड़ने लगेगा – मंदी और बढ़ेगी। मुनाफे की अंधी हवस का यह एक ऐसा दुश्चक्र है कि वे इसमें उलझते चले जा रहे हैं, और अपने अन्त की ओर कदम बढ़ाते जा रहे हैं। यह भी इतिहास की एक सच्चाई है कि इन लुटेरों का अन्त खुद ब खुद नहीं होगा। इनके अन्तिम क्रियाकर्म की तैयारी तो मज़दूर आबादी को ही करनी पड़ेगी – अन्तिम और फैसलाकुन जंग की लम्बी तैयारी। और तब मेहनतकशों का जो वेगवाही तूफान उठेगा, उसके थपेड़ों से वे गहरी खाई में दफ्न हो जायेंगे।

जन्मदिन (22 अप्रैल) के अवसर पर

लेनिन के साथ दस महीने

– एल्बर्ट रीस विलियम्स

एल्बर्ट रीस विलियम्स उन पांच अमेरिकी जनों में से एक थे जो अक्टूबर क्रान्ति के तूफानी दिनों के साक्षी थे। वे 1917 के बसंत में रूस पहुंचे। उस समय से लेकर अक्टूबर क्रान्ति तक, वे तूफान के साक्षी ही नहीं बल्कि भागीदार भी रहे। इस दौरान उन्होंने व्यापक जनता के शौर्य एवं सृजनशीलता के साथ ही बोल्शेविक योद्धाओं के जीवन को भी निकट से देखा। लम्बे समय तक वे लेनिन के साथ-साथ रहे। क्रान्ति के बाद जुलाई, 1918 तक उन्होंने दुनिया भर की प्रतिक्रियावादी ताकतों से जूझती पहली सर्वहारा सत्ता के जीवन-संघर्ष को निकट से देखा।

स्वदेश लौटकर रीस विलियम्स ने दो किताबें लिखीं – **'लेनिन: व्यक्ति और उनके कार्य'** तथा **'रूसी क्रान्ति के दौरान'**। ये दोनों पुस्तकें एक जिल्द में **'अक्टूबर क्रान्ति और लेनिन'** नाम से राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ से प्रकाशित हो चुकी हैं।

लेनिन के जन्मदिवस के अवसर पर हम रीस विलियम्स की पूर्वोक्त पहली पुस्तक का एक हिस्सा 'बिगुल' के पाठकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

– संपादक

4. लेनिन के व्यक्तिगत जीवन में कठोर अनुशासन

लेनिन सामाजिक जीवन में जिस कठोर अनुशासन की भावना का संचार कर रहे थे, उसी प्रकार वे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कठोर अनुशासन का पालन करते थे। श्ची और बोर्श्च (दो प्रकारों के शोरबे जो चुकन्दर और आलू से तैयार होते हैं), काली रोटी के टुकड़े, चाय और दलिया- यह स्मोल्नी में आने वालों का आहार था। लेनिन, उनकी पत्नी और बहन का भी यही भोजन होता था। क्रान्तिकारी प्रतिदिन 12 से 15 घंटे तक अपने काम पर डटे रहते थे। लेनिन प्रतिदिन 18 से 20 घंटे तक काम करते थे। वे अपने हाथ से सैकड़ों पत्र लिखते थे। काम में संलग्न वे अन्य किसी बात की, यहां तक कि अपने खाने-पीने की भी कोई चिंता नहीं करते थे। लेनिन जब बातचीत में खोये होते, तो इस अवसर का लाभ उठाकर उनकी पत्नी चाय का गिलास हाथ में लिये वहां आकर कहतीं, "कामरेड, यह चाय रखी है, इसे पीना न भूल जाइएगा।" चाय में अक्सर चीनी न होती, क्योंकि लेनिन भी शेष लोगों की भांति राशन में जितनी चीनी पीते थे, उसी पर गुजर करते थे। सैनिक और संदेशवाहक बड़े-बड़े खाली और बैरक-सदृश्य कमरों में लोहे की चारपाइयों पर सोते थे। लेनिन और उनकी पत्नी भी इसी प्रकार की चारपाइयों पर सोते। वे थके-मांदे कड़े पलंग पर सो रहते और किसी भी आकस्मिक घटना या संकट के समय तत्काल उठ बैठने के ख्याल से अक्सर कपड़े भी नहीं उतारते थे। लेनिन ने किसी तपस्वी की भावना से इन कष्टों को झेलने का व्रत ग्रहण किया था। वे तो केवल कम्युनिज्म के प्रथम सिद्धांतों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान कर रहे थे।

इनमें एक सिद्धांत यह था कि किसी भी कम्युनिस्ट अधिकारी का वेतन एक सामान्य मजदूर के वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए। शुरू में अधिकतम वेतन 600 रूबल निर्धारित किया गया था। बाद में इसमें कुछ वृद्धि हुई। इस समय सोवियत रूस के प्रधानमंत्री को प्रतिमास 200 डालर से कम वेतन मिलता है।

लेनिन ने जब 'नेशनल' होटल की दूसरी मंजिल में अपने लिए कमरा लिया, तो उस समय मैं भी वहीं ठहरा हुआ था। सोवियत शासन का प्रथम कदम लम्बी और बहुत खर्चीली व्यंजन-सूची निश्चित हुई। कोई भी व्यक्ति भोजन में शोरबा और गोश्त अथवा शोरबा और **काशा** (दलिया) ले सकता था। और कोई भी व्यक्ति चाहे वह जन-कमिसार हो, अथवा रसोईघर में काम करनेवाला हो, उसे यही भोजन मिल सकता था, क्योंकि कम्युनिस्टों के सिद्धांत में यह बात अंकित है कि "जब तक प्रत्येक व्यक्ति को रोटी न मिल जाय, तब तक किसी को भी केक सुलभ न होगा।" ऐसे दिन भी आते जब लोगों के लिए रोटी की भी कमी पड़ जाती। तब भी लेनिन को उतनी ही रोटी मिलती थी, जितनी प्रत्येक व्यक्ति को। कभी-कभी तो बिल्कुल रोटी न होती। उन दिनों लेनिन को भी रोटी नहीं मिलती थी।

लेनिन की हत्या करने के प्रयास के बाद जब मृत्यु उनके सिर पर मंडराती प्रतीत होती, तो डाक्टरों ने उनके लिए खाने-पीने की कुछ ऐसी चीजें निर्दिष्ट कीं, जो नियमित भोजन-कार्ड के अनुसार सुलभ नहीं थीं और जो बाजार में किसी मुनाफाखोर से ही खरीदी जा सकती थीं. अपने दोस्तों के तमाम अनुनय-विनय के बावजूद उन्होंने किसी ऐसे खाद्य-पदार्थ को स्पर्श करने से भी इनकार कर दिया, जो वैध राशन-कार्ड का अंग न हो।

बाद में जब लेनिन स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, तो उनकी पत्नी और बहन ने उनके भोजन की मात्रा बढ़ाने की एक तरकीब निकाली। यह देखकर कि वे अपनी रोटी मेज की दराज में रखते हैं, वे उनकी अनुपस्थिति में चुपके से उनके कमरे में जातीं और जब-तब रोटी का अतिरिक्त टुकड़ा उसी दराज में डाल देती। अपने काम में लीन लेनिन यह जाने बिना ही कि रोटी का वह टुकड़ा नियमित राशन से अधिक है, उसे मेज की दराज से निकाल कर खा लेते।

लेनिन ने यूरोप और अमरीका के मजदूरों के नाम अपने एक पत्र में लिखा, "रूस की जनता ने कभी भी इतने कष्ट, भूख की इतनी पीड़ा सहन नहीं की थी जैसा कि इस समय मित्रराष्ट्रों के फौजी हस्तक्षेप के कारण भोग रही है।" इन सारी कठिनाइयों को लेनिन भी जनता के साथ झेल रहे थे।

लेनिन के विरुद्ध एक महान राष्ट्र के जीवन के साथ जुआ खेलने और व्याधिग्रस्त रूस पर एक प्रयोगवादी की भांति प्रमादपूर्ण ढंग से अपने कम्युनिस्ट सूत्रों को लागू करने का आरोप लगाया गया है। परन्तु इन सूत्रों में विश्वास के अभाव का आरोप उनके विरुद्ध नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने केवल रूस पर नहीं, बल्कि अपने ऊपर भी इन सूत्रों का प्रयोग किया। उन्होंने दूसरों को जो औषधि दी, वह स्वयं भी पी। दूर से कम्युनिज्म के सिद्धांतों के प्रति आस्था प्रकट करना एक बात है, परन्तु लेनिन की भांति कम्युनिस्ट सिद्धांतों को कार्यान्वित करने में कष्टों और दारुण स्थितियों का सामना करना बिल्कुल दूसरी ही बात है।

फिर भी, कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना के प्रारम्भिक दिनों को पूर्णतया धुंधले रंगों में चित्रित नहीं करना चाहिए। रूस में उन घोर अंधकारपूर्ण दिनों में भी कला फल-फूल रही थी और संगीत-नाट्य प्रस्फुटित हो रहा था। उस परीक्षा की घड़ी में भी रोमांस ने जीवन में अपनी भूमिका अदा की। क्रान्तिकारी मंच के मुख्य नायक भी इससे अछूते न रहे। एक रोज सुबह यह जानकर हम अभिचकित रह गये कि बहुमुखी प्रतिभाशाली कोल्लोन्ताई ने नाविक दिबेन्को से शादी कर ली है। बाद में नार्वा में जर्मनों से मोर्चा लेने की जगह पीछे हटने का आदेश देने के कारण उसकी भर्त्सना की गयी। वह कलंकित होकर पद और पार्टी से हटा दिया गया। लेनिन ने इसका अनुमोदन किया। कोल्लोन्ताई का रोष में होना तो स्वाभाविक था।

इस अवसर पर कोल्लोन्ताई से बातचीत करते हुए मैंने यह मत प्रकट किया कि सभी मनुष्यों की तरह लेनिन भी शक्ति के नशे में चूर मदान्ध हो गये हैं और उनकी अहमन्यता बढ़ गयी है। उन्होंने उत्तर दिया, "इस समय गुस्से में होते हुए भी मैं वह कदापि नहीं सोच सकती कि किसी व्यक्तिगत उद्देश्य से वे कोई कार्य कर सकते हैं। कोई भी साथी, जिसने कामरेड लेनिन के साथ 10 वर्षों तक काम किया है, यह विश्वास नहीं कर सकता कि स्वार्थ उन्हें छू भी गया है।"

शेष अगले अंक में

अक्टूबर क्रांति की 82वीं वर्षगांठ के अवसर पर राहुल फाउण्डेशन की नई प्रस्तुति

अक्टूबर क्रान्ति और लेनिन

सोवियत समाजवादी क्रान्ति की तैयारी से लेकर बाद के दौर तक वहां उपस्थित रहकर युगान्तरकारी घटनाओं के साक्षी रहे अमेरिकी पत्रकार एल्बर्ट रीस विलियम्स की दो दुर्लभ कृतियां :

'रूसी क्रान्ति के दौरान' तथा **'लेनिन : व्यक्ति और उनके कार्य'** एक ही जिल्द में हिन्दी पाठकों के लिए विशेष रूप से

साथ ही रीस विलियम्स का परिचय

मूल्य : रु. 75/- (पेपर बैक) रु. 150/- (सजिल्द)

एल्बर्ट रीस विलियम्स की कृतियां क्रान्तिकारी दौर की घटनाओं में उनके असली नायक आम जन समुदाय के कारनामों और सोच को सामने लाती है तथा लेनिन के मानवीय, जीवन्त और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का प्रामाणिक प्रभावी चित्र प्रस्तुत करती है जिनके साथ उन्हें लम्बे समय तक रहने का अवसर मिला था।

प्राप्त करें :

जनचेतना

डी-68, निराला नगर, लखनऊ-226 020

पंजीयन संख्या - 71980/99 डाक पंजीयन संख्या - LW-NP/349/2000

नारी सभा

जो पैदा होंगी हमारे बाद

यह मत कहो बहनो कि तुम कुछ नहीं कर सकतीं
आस्था की कमी अब और नहीं
हिचक अब और नहीं
आओ, पूछें अपने आप से
क्या चाहते हैं हम?

पूर्ण मुक्ति चाहिए, नहीं चाहते कम,
उड़ाने दो माखौल उन्हें, रुक जाएगी हंसी एक दिन
वे दिन क्या दूर हैं?
क्या फर्क पड़ता है उससे!

संघर्षों में झेलनी हैं दिक्कतें और तकलीफें हमें
सुख उन बहनों के लिए होगा, जो पैदा होंगी हमारे बाद।

अज्ञात

मेरे क्रोध की लपटें

एक फिलिस्तीनी स्त्री

तुमने मुझे बांधा है
जकड़ा है जंजीरों से
पर लपटें मेरे क्रोध की
धधकती हैं, लपकती हैं।
नहीं कोई आग इतनी तीखी
क्योंकि मेरी पीड़ा के ईंधन से
ये जीती हैं, पनपती हैं।

आग को ठंडाने के लिए
हंस सकती हूं मैं भी
उन लोगों की ताकत पर
हैं नहीं जो इंसान
कहलाने के काबिल भी।

शरीर बांध सकते हो
चेनों से, जंजीरों से
शब्दों को बन्दी
बनाना नहीं मुमकिन
वो तो उड़ जाएंगे
मुक्त पंछियों से।

(अनुवाद: वीणा शिवपुरी)

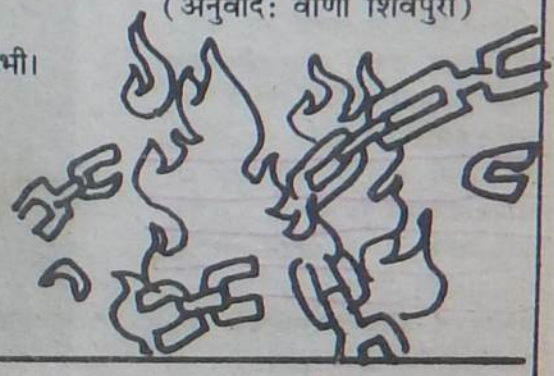

मुर्गे और दारू के जश्न के बीच मज़दूर रहनुमाई का ढकोसला

बिगुल संवाददाता

नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल का खुशनुमा मौसम, आरिफ कैसेल जैसे महंगे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल, नील-टीनोपाल से चमचमाते श्वेत देशी वस्त्र (कुर्ता-पायजामा), हाथों में मोबाइल फोन, इम्पोर्टेड कारें, लंच- ब्रेकफास्ट-डिनर में मुर्गे की उड़ती टांगें और इम्पोर्टेड दारू और कुर्सियों के खींचतान के बीच मज़दूर हितों पर चिंता प्रकट करने और उनके संघर्षों का दावा करने का क्या खूबसूरत सम्मिश्रण था भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस (इंटक) के राष्ट्रीय कार्यसमिति की वार्षिक बैठक का!

लाखों रुपये पानी की तरह बहाकर जिस वक्त इन तथाकथित मज़दूर रहनुमाओं का जश्ने जम्हूरियत नैनीताल में चल रहा था, यहां से कुछ किलोमीटर दूर काशीपुर में सलोरा कारखाने की तालाबन्दी से मज़दूर अस्तित्व का संघर्ष कर रहे थे। इस राष्ट्रीय बैठक में सलोरा का मुद्दा छूने की भले ही फुर्सत न रही हो पर वरिष्ठ कांग्रेसी दिग्गज और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नारायण दत्त तिवारी ने श्रमिकों की प्रतिदिन होती दयनीय स्थिति और उद्योगों की बन्दी पर घड़ियाली आंसू जरूर बहाये। इंटक नेताओं की चिन्ता निजीकरण की नहीं थी, बल्कि इसके प्राथमिकताओं की

थी। मसलन उनके अनुसार पहले बीमार और घाटे वाले उद्योग बन्द होने चाहिए।

इस कांग्रेसी मज़दूर महासंघ इंटक से उम्मीद ही क्या की जा सकती है? इनका इतिहास ही गद्दारियों से भरा रहा है। जिस वक्त इस देश के मज़दूर कर्मचारी देश के एकमात्र और लड़ाकू महासंघ के नेतृत्व में अपने एकताबद्ध जुझारू संघर्ष कर रहे थे, तब उनके आन्दोलनों को तोड़ने-भ्रमित करने के लिए इंटक का गठन हुआ था। 60' और 70' के दशक में जब बैंक के राष्ट्रीयकरण की मांग से लेकर रेलवे तक के जबर्दस्त आंदोलन संगठित हो रहे थे तब इंटक का पुनर्गठन हुआ और उनके आन्दोलनों में इसने भितरघात किया। 74' के ऐतिहासिक रेल आंदोलन में इन 'लायलों' (मज़दूर भाषा में गद्दारों) को भला कौन भूल सकता है। (वैसे इस रेल आन्दोलन के प्रमुख नेता और वर्तमान रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडीज के ऐतिहासिक गद्दारी को, जिसने रेलवे कर्मियों की कमर तोड़ दी, भी मज़दूर नहीं भूल सकेगा)।

वैसे भी, मज़दूरों-कर्मचारियों की इस तबाही-बर्बादी की मुख्य जिम्मेदार तो इंटक की मां कांग्रेस ही रही है। पूंजीपतियों की हितसाधक कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई ऊपर के 10-15 फीसदी धनिकों के लिये ही लड़ी थी। सन 47' में आज़ादी उन तक ही सीमित रही और नीतियां भी उनके लिये ही बनी। सन 90' से जारी मज़दूर विरोधी आर्थिक नीतियों को इसने ही लागू किया था – निजीकरण-छंटनी-तालाबन्दी का नया दौर इसने ही शुरू किया था, आम जनता की तबाही-बर्बादी का साजो-सामान इसने ही जुटाया था। बाद की सरकारों ने इसे आगे बढ़ाया और भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार ने इसे सरपट दौड़ा दिया। तब भला मज़दूर-कर्मचारी इंटक से उम्मीद पाले ही क्यों? वह तो मज़दूरों के खून से सने इन महासंघी हाथों को काटने की तैयारी करेगा।

बाल्को के मज़दूर आन्दोलन को बेचने के बाद सैर-सपाटे के लिये पहुंचे इंटक नेताओं के चेहरे पर वही चिरस्थायी बेहयाई व्याप्त थी। 'सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली।' इन भितरघातियों की निगाह अब नये उत्तरांचल राज्य पर है। इस बार नैनीताल में इनके जमावड़े का मुख्य उद्देश्य यही था। इंटक के दिग्गज मठाधीशों ने नये राज्य में कइयों को पद बांट रखे हैं और इनकी गिद्ध दृष्टि अब उत्तरांचल के तमाम कारखानों पर है। मज़दूरों को इन भेड़ियों से सावधान रहना होगा।

रंगे सियारों, बगुला भगतों और जहरीले सांपों का जमावड़ा है लोक मोर्चा

बिगुल प्रतिनिधि

गोरखपुर। तहलका डॉट कॉम भण्डाफोड़ ने पूंजीवादी राजनीति के सभी रंगे सियारों, बगुला भगतों और जहरीले सांपों को एकजुट होने का एक बहाना मुहैया करा दिया है। जनता के बीच नैतिकता और सदाचार के ढिंढोरची 'स्वदेशी' रामभक्तों की मंडली की मटियामेट हो गयी छवि से चुनावी लाभ बटोरने की आस में एक नया लोक (विरोधी) मोर्चा पिछले 3 अप्रैल को पैदा हो गया है।

इस मोर्चे के झंडाबरदारों की 'हम चलेंगे साथ-साथ' वाली मुद्रा में छपी फोटो पूंजीवादी अखबारों के पहले पन्ने पर सबने ज़रूर देखी होगी। यह पिछले 17 अप्रैल को आज़मगढ़ में आयोजित मोर्चे की पहली रैली के मंच का नजारा था। रैली में मोर्चे के संयोजक मुलायम सिंह यादव, हरिकिशन सिंह सुरजीत, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी.देवगौड़ा, ए.बी. वर्धन, जनेश्वर मिश्र और अमर सिंह जैसों ने मंच से भ्रष्टाचारी राजग सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान इस अन्दाज में किया जैसे ये सब सदाचार के पुतले और नैतिकता के साक्षात अवतार हों।

सत्तारुढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन के नेताओं के भ्रष्टाचार, दोगलेपन, झूठ-फरेब, बेहयाई और जनविरोधी नीतियों से जनता के भीतर जो गुस्सा और नफ़रत जमा होती जा रही है उसे चुनावी लहर में बदल देने का मंसूबा बांधते हुए लोक मोर्चा में शामिल पार्टियां कुर्सी तक पहुंचने का ख्वाब देख रही हैं। इनके नेताओं को इस बात का भरोसा है कि 'तहलका' से उठे गर्द-गुबार में इनके चेहरों पर पुती कालिख जनता को नज़र नहीं आयेगी और वे अगले लोक सभा चुनाव की वैतरणी पार लगा जायेंगे।

इन नेताओं को इस बात का भरोसा एक बार फिर जाग उठा है कि विकल्पहीनता और कमजोर राजनीतिक याद्दाश्त के चलते जनता इनकी राजनीतिक जन्मकुंडली भूल जायेगी। वह भूल जायेगी कि मोर्चे में शामिल पार्टियां (समाजवादी पार्टी, भाकपा, माकपा, जनता दल-सेक्युलर और अन्य) वही हैं जो पुराने संयुक्त मोर्चा की घटक थीं। जिस मोर्चे की सरकार भी देवगौड़ा और गुजराल की अगुवाई में उन्हीं जनविरोधी नीतियों पर चलती रही है जिस पर मौजूदा राजग सरकार चल रही है और कांग्रेस जिसकी सूत्रधार रही है।

लेकिन देश की मेहनतकश जनता को किसी भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। पूंजीवादी राजनीति के घाघ विश्वनाथ प्रताप सिंह के मसीहाई मुखौटे के झांसे में भी आने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि मेहनत की लूट पर टिके इस समूचे पूंजीवादी लूट तंत्र को उखाड़ फेंकने की तैयारी तेज की जाये। एक मजबूत क्रान्तिकारी विकल्प को तैयार करना ही एकमात्र विकल्प है।

मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी डा. दुधनाथ द्वारा 69, बाबा का पुरवा, निशातगंज, लखनऊ से प्रकाशित एवं उन्हीं के द्वारा वाणी प्राफिक्स, अलीगंज, लखनऊ से मुद्रित। कम्पोजिंग : कम्प्यूटर प्रभाग, राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ।
संपादक मण्डल : डा. दुधनाथ, मुकुल। सम्पादकीय पता : 69, बाबा का पुरवा, पेपर मिल रोड, निशातगंज, लखनऊ-226006, सम्पादकीय उपकार्यालय : जनगण होम्यो सेवासदन, मर्यादपुर, मऊ।